Ok"k % 40(vad % 05 (ebZ % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

सीटू की ओर से अपने सभी पाठकों को मई दिवस की शुभकामनायें

विशाखापट्टनम स्टील मार्च

उमड़ा लाल सैलाब

(रिपोर्ट पृ० 14)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

(रिपोर्ट पृ० 16)

ओडिशा विधान सभा के सामने धरना

(रिपोर्ट पृ० 23)

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk

e[kiw=

मई 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

मई दिवस का घोषणा पत्र, 2018 — 5

मई दिवस–2018 — 8
डब्ल्यू एफ टी यू का आहवान

श्रम और संसदीय जनतंत्र — 10
–बी.आर.अंबेडकर का भाषण

मोदी सरकार की झूठी व भ्रामक बयानबाजी — 12
–जे एस मजुमदार

उद्योग व क्षेत्र — 14

किसान आंदोलन — 18

राज्यों से — 20

अंतर्राष्ट्रीय — 25

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक — 26

सम्पादकीय

लोकतंत्र और अधिकारों की हिमायत में

चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस की मिलीभगत से , पंचायत चुनावों की तारीख एक मई घोषित किये जाने के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फैडरेशनों ने मिलकर पश्चिम बंगाल चुनाव आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया व मांग की कि 1 मई चूकिं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है इसलिए चुनाव की तारीख पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए। ट्रेड यूनियने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी गयी हैं।

सीटू ने चुनावों की तारीखें पुनर्निर्धारित किये जाने की ट्रेड यूनियनों की मांग का समर्थन किया है व मजदूर दिवस मनाने के मजदूरों के अधिकार पर राज्य सरकार के हमले तथा टीएमसी के गुंडों को संरक्षण देकर पंचायत चुनावों में हिंसा तथा धांधली की भर्त्सना की है। पंचायत चुनावों के सन्दर्भ में पश्चिम बंगाल में घटित हो रहा यह घटनाविकास मजदूरों द्वारा कठिन संधर्षो से हासिल उनके अधिकारों तथा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर हमला है।

यह पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के माध्यम से जमीनी स्तर तक लोकतंत्र की आदर्श आधारशिला रखी थी। यही आदर्श बाद में 1992 में 'पंचायतें' शीषर्क से नौवीं अनुसूची में 29 वे विषय के रूप में 73 वे संविधान संशोधन के जरिये भारत के संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 74 वे संशोधन के रूप में नगरपालिकाओं के लिए प्रभावी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय तक ने इसे रेखांकित किया और कहा कि भारतीय लोकतंत्र के तीन खम्भे – लोकसभा, विधानसभा और पंचायत – हैं। एकदम जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को पहुंचाने के वाम मोर्चे के इस योगदान ने भारतीय राजनीति पर जो दूरगामी असर डाले हैं उनके महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। अमल और व्यवहार में उतारने में कई सीमाओं और कमजोरियों के बावजूद इसने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के बीच मन्थन पैदा किया जिसकी प्रतिछाया इन तबकों के बीच देशभर के गाँवों में उभर रहे प्रतिरोध के रूप में दिखाई देती है।

जमीनी स्तर तक के लोकतंत्र का यह वामपंथी आदर्श पश्चिम बंगाल की तानाशाह सरकार के हमलों के निशाने पर है। सरकार और प्रशासन की ताकत के जरिये वह पंचायत चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रही है, उसका लम्पटीकरण कर रही है और वंचित तथा शोषित तबकों को कुचलने की कोशिश कर रही है। ठीक यही बर्ताव मजदूरों तथा समूची जनता के मुक्ति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस,मई दिवस मनाने के अधिकार को लेकर है।

भले पंचायत चुनाव राज्य के कानून के तहत होते हैं, किन्तु इनकी प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में वर्णित है। इस कानून की धारा 135 (बी) कहती है कि प्रत्येक रोजगारशुदा व्यक्ति को इस दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। वही दूसरी ओर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मजदूरों को मई दिवस मनाने के लिए इस दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। एक को दूसरे से हटाया नहीं जा सकता। ना ही किसी दूसरी छुट्टी के साथ इसकी पूर्ति की जा सकती है। क्योंकि यह छुट्टी भर का मसला नहीं है, उस आयोजन का – मई दिवस का – है जिसके लिए अवकाश दिया जाता है।

सीटू स्थापना दिवस की शपथ

30 मई, 2018

सीटू के इस 48वें स्थापना दिवस पर;

– हम, नवउदारवाद के हमलों से मजदूरों के मुश्किल व कड़े संधर्षो के बल पर हासिल किये गये हकों व उनके काम व जीवन यापन के हालातों में सुधार की मांगों पर और अधिक दम–खम के साथ संधर्ष जारी रखने के लिए अपने आपको समर्पित करते हैं;

– एक शोषणविहीन समाज के तथा सभी मेहनतकशों के लिए एक अच्छे व सम्मानजनक जीनव के सीटू के संविधानिक उद्देश्य को पाने के लिए सीटू को मजबूत करने की शपथ लेते हैं;

– हम, इस लक्ष्य की प्राप्ति के संधर्ष में, धर्म, जाति, क्षेत्र व लैंगिक विभाजन से पार जाकर समूचे मजदूर वर्ग को एकजुट करने की शपथ लेते हैं;

– हम मेहनतकशों के व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर जारी हमलों का प्रतिरोध करने के लिए संधर्ष को शक्तिशाली व व्यापक बनाने की शपथ लेते हैं;

– हम, किसी भी बहाने से मेहनतकशों की एकता को तोड़कर, उनके हालातों को बेहतर करने के संधर्ष को कमजोर करने के प्रयासों का प्रतिरोध व उन्हें परास्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

एक बेहतर भविष्य के लिए एक हों, संघर्ष करें

केरल में वाम जनवादी मोर्चे की वैकल्पिक नीति-एक मील का पत्थर

प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कदम:

केरल ने उदाहरण प्रस्तुत किया

दुर्घटना में मृत्यु	रू० 50,000
घातक बीमारियों का ईलाज	रू० 25,000
टर्मिनल लाभ	रू० 10,000 से 25,000
बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान	रू० 1000– रू० 3000
मूल निवास स्थान तक मृत शरीर को ले जाने हेतु	रू० 5000– रू० 15,000
मातृत्व लाभ	रू० 15,000

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस

मई दिवस घोषणापत्र, 2018

मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के दिवस, इस मई दिवस पर;

सीटू–

- दुनिया भर के मेहनतकश अवाम का अभिनंदन करता है, फिर चाहे वह फैक्टरियों में काम कर रहा हो, कार्यालयों में, सेवाओं में, खदानों में, वनों में, खेतों में काम कर रहा हो या समंदर में।
- सीटू कड़े संघर्षों से हासिल किए गए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, जीवन स्थितियों में सुधार के लिए, साम्राज्यवाद की अगुवाईवाले हमलों को मात देने के लिए, उनके जीवन तथा रोजी–रोटी पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त द्वारा संचालित पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा खासतौर से व्यवस्थित विश्विक संकट की पृष्ठभूमि में किए जा रहे हमलों को मात देने के लिए और हर तरह के शोषण से अपनी मुक्ति के लिए किए जा रहे उनके तमाम संघर्षों के साथ एकजुटता का इजहार करता है।
- सीटू समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्घता को और मनुष्य द्वारा मनुश्य के शोषण से मुक्त समाज के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराता है और अपने देशों में समाजवाद की रक्षा के प्रयासों में लगी समाजवादी देशों की जनता के साथ एकजुट होकर खड़ा है।
- सीटू बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जनतांत्रिक ढ़ंग से अपनी सरकारें चुनने के तमाम देशों की जनता के अधिकारों का पक्ष लेता है, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों और अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, इराक आदि देशों में साम्राज्यवादी युद्घों की और लातीनी अमरीका तथा दुनिया के दूसरे हिस्सों में वामपंथी–प्रगतिशील सरकारों को कमतर बनाने की उनकी प्रभुत्ववादी साजिशों की निंदा करता है और अपनी पूरी ताकत से साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का वचन देता है और जोर देकर यह बात कहता है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष शोषण के खिलाफ वर्गीय संघर्ष का अभिन्न हिस्सा है।
- सीटू अपने होमलैंड के लिए फिलिस्तीनियों के बहादुरीपूर्ण संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता दोहराता है और 1967 की सीमाओं और पूर्वी येरूशलम को उसकी राजधानी मानते हुए एक स्वतंत्र संप्रभू फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने की मांग करता है।

सीटू–

- नव–उदारवाद के तहत बढ़ती असमानताओं को गहरी चिंता के साथ नोट करता है, जहां 1 फीसद सबसे अमीर लोग, दुनिया की उस आधी से ज्यादा दौलत को कब्जाए बैठे हैं, जो शोषित–पीड़ित जनता की खून पसीने से पैदा हुयी है। उन्होंने यह दौलत मेहनतकश अवाम के शोषण में बढ़ोतरी करके, दरबारी पूंजीवाद को बढ़ावा देकर, करों की चोरी करके और सार्वजनिक परिसंपत्तियों तथा गरीब किसानों, आदिवासियों तथा दूसरे लोगों को उजाडकर प्राकृतिक संसाधनों–जमीनों, वनों, खदानों तथा पानी को हड़प कर बनायी है।
- सीटू दक्षिणपंथी शक्तियों के उभार पर अपनी चिंता का इजहार करता है, जो नव–उदारवाद का कोई विकल्प नहीं पेश करती बल्कि राष्ट्रीयताओं, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, जाति, लिंग और दूसरे तरीकों से दुनिया के अनेक हिस्सों में मजदूर वर्ग तथा शोषित–पीडित जनता को विभाजित करना चाहती हैं। ऐसा उन देशों में ज्यादा स्पष्ट है, जहां तथाकथित सामाजिक जनतांत्रिक और वामोन्मुखी शक्तियों ने नव–उदारवादी नीतियों का समर्थन करने के जरिए मजदूर वर्ग के साथ दगा किया है।
- सीटू इस बात की ताईद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित ये दक्षिणपंथी शक्तियां विभिन्न तरीकों के जरिए शोषित–पीड़ित जनता की एकता को तोडकर और नव–उदारवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को कम करके बड़े कार्पोरेट तथा व्यापारिक घरानों के ही हित साधती हैं। सीटू उन्हें शोषित–पीड़ित जनता के दृश्मन करार देता है।
- सीटू जोर देकर यह बात कहता है कि मौजूदा संदर्भ में पूंजीवाद के लिए यह जरूरी हो गया है कि निरंतर गहराते संकट की अपनी मौजूदा स्थिति में पूंजीपतियों के मुनाफों की रक्षा के लिए और मौजूदा व्यवस्था के संकट में अपने को बचाए रखने के लिए वह दक्षिणपंथी, तानाशाही और बर्बरतावादी ताकतों को आगे बढ़ाए। मजबूत समाजवादी ब्लॉक की अनुपस्थिति से वह प्रोत्साहित होता है।

- सीटू इस बात की निंदा करता है कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था, जनता की सक्रिय भागीदारी से हुयी विज्ञान तथा तकनीक की भारी प्रगति का इस्तेमाल उनके लाभ के लिए नहीं बल्कि कुछ विकसित देशों, बड़े कार्पोरेट तथा व्यापारिक घरानों को समृद्घ करने के लिए कर रही है जो इनके मालिक बन बैठे हैं।
- सीटू बेरोजगारी, गरीबी, बदहाली, अशिक्षा, बीमारी, आवास की कमी और जनता के व्यापक बहुमत की बुनियादी जरूरतों के अभी भी बने रहने बल्कि उनके बढने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराता है। यह स्थिति इसके बावजूद है कि इन्हें खत्म करने के तमाम आवश्यक संसाधन आज मौजूद हैं।
- सीटू पूंजीवादी व्यवस्था की अंतर्निहित शोषणकारी प्रकृति के बारे में मजदूर वर्ग के बीच जागरूकता बढ़ाने की शपथ लेता है, जो जारी संकट के और बढ़ जाने की पृष्ठभूमि में ज्यादा तीखा, भयावह और बर्बर हो गया है। सीटू पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में मजदूर वर्ग की भूमिका के बारे में और हर तरह के शोषण के खात्मे के लिए अंतिम संघर्ष के लिए उन्हें तैयार करने के लिए मजदूरों की चेतना बढ़ाने की शपथ लेता है।
- सीटू, दुनिया भर के मजदूर वर्ग को एकजुट करने के उसके प्रयासों में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (डब्लू एफ टी यू) को मजबूत बनाने तथा और ज्यादा वर्गोन्मुखी दृढ़ निश्चय के साथ शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने के अपने दृढ़ निश्चय की घोषणा करता है।

इस मई दिवस पर सीटू–

- देश के मेहनतकश अवाम पर तितरफा हमलों –भाजपा निजाम द्वारा मजदूर वर्ग पर जारी नव–उदारवादी हमलों और हमारे देश की जनता की जीवन स्थितियों पर हमलों, सरकार के तकरीबन तमाम संस्थानों और विभिन्न सामाजिक संस्थानों पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगे आर एस एस के साथ विभाजनकारी सांप्रदायिक तथा जातिवादी ताकतों के बढ़ते प्रभाव और बढ़ती तानाशाही, समाज में बढ़ती असहिष्णुता, जहां तार्किक तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देनेवाले लोगों पर शारीरिक हमले किए जा रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही है, भाजपा की नीतियों तथा विचारों और विचारधारा पर किसी तरह की असहमति रखनेवालों और उनका विरोध करनेवालों को ''देशद्रोही'' करार दिया जा रहा है और गाली–गलौच, धमकियों तथा शारीरिक हमलों के जरिए उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही है–पर गहरी चिंता व्यक्त करता है।
- सीटू बढ़ती बेरोजगारी, रोजगारहीनता और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में गहराते अंधकार, बढ़ती दरिद्रता, कृषि संकट, ग्रामीण बदहाली और किसानों की निरंतर जारी आत्महत्याओं और नव–उदारवादी व्यवस्था के तहत अश्लील ढ़ंग से असमानताओं के बढ़ने पर गहरी चिंता दर्ज कराता है।
- सीटू आंखें खोल देनेवाली विडंबना और साथ ही साथ सरकार के पाखंड को सामने लाता है, जो ''राष्ट्रवाद'' की बातें करके देश की दौलत–जमीनों, वनों, जल संसाधनों, खदानों तथा रणनीतिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों–को 100 फीसद एफ डी आइ के जरिए विदेशी निगमों के हवाले करने के जरिए पूरी तरह से देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है।
- यह ऐसी सरकार है, जो राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करती है और राष्ट्रीय गौरव को बुलंद रखने का दावा करके अमरीकी साम्राज्यवाद की जूनियर रणनीतिक हिस्सेदार बनने के जरिए स्वतंत्र विदेशी नीति को कुर्बान करती है।
- सीटू ''कारोबार की राह आसान बनाने'' की बजाय '' मजदूर वर्ग की संगठित शक्ति, ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने और उन्हें खत्म करने के अंतिम इरादे के साथ जनता और देश की लूट को आसान बनाने'' को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम सुधारों के नाम पर श्रम अधिकारों पर हमलों को जारी रखने की निंदा करता है। सीटू मजदूर वर्ग पर दासता थोपने का प्रतिरोध करने और दृढ़ता के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्घता को दोहराता है।
- सीटू त्रिपुरा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद वामपंथी पार्टियों और सीटू के कार्यालयों तथा कार्यकर्ताओं पर भाजपायी गुंडों के हमलों की निंदा करता है। वहां लेनिन की प्रतिमा को ढ़हा दिया गया। सीटू यह मांग करता है कि ये हमले फौरन रोके जाएं।
- सीटू त्रिपुरा की जनता और मजदूर वर्ग को सलाम करता है और उनके साथ एकजुटता का इजहार करता है, जो बहादुरी के साथ इन हमलों का प्रतिरोध कर रहे हैं। सीटू यह विश्वास व्यक्त करता है कि त्रिपुरा की जनता जल्द ही इन हमलों से उबर जाएगी।
- सीटू पश्चिम बंगाल में तृणमूली गुंडों द्वारा वामपंथ तथा सीटू के कार्यकर्ताओं पर निरंतर किए जा रहे और खासतौर से पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि में किए जा रहे हमलों की निंदा करता है। सीटू पूरे मजदूर वर्ग तथा जनतांत्रिक आंदोलन द्वारा किए जा रहे सारे विरोध को दबाते हुए मई दिवस के दिन पंचायत चुनाव कराए जाने के तृणमूली सरकार के निर्णय की निंदा करता है। वामपंथी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर शारीरिक हमले किए गए हैं और उन्हें राज्य में होनेवाले आगामी पंचायत चुनावों के लिए अपनी नामजदगी के पर्चे भरने से रोका गया है। सीटू इन घृणित हमलों का प्रतिरोध कर रही जनता के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करता है।

- सीटू देश के विभिन्न हिस्सों में और खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों पर अपने गुस्से का इजहार करता है। प्रतिगामी और ऊंच–नीच को माननेवाली मनुस्मृति, जो दलितों, आदिवासियों तथा महिलाओं को दबाना चाहती है, के प्रति भाजपा और आर एस एस की विचारधारात्मक प्रतिबद्घता इस तरह के हमलों को प्रोत्साहित करती है। मनुस्मृति के प्रति अपनी प्रतिबद्घता को बनाए रखते हुए भाजपा सिर्फ अपने चुनावी लाभों के लिए दलितों को लुभाना तथा बरगलाना चाहती है।
- सीटू अपने संवैधानिक तथा जनतांत्रिक अधिकारों के आग्रहशील होते हुए और अपने जीवन तथा रोजी–रोटी पर हो रहे हमलों का प्रतिरोध करते हुए जनता के विभिन्न तबकों–मजदूरों, किसानों, दलितों, छात्रों आदि के बढ़ते संघर्षों का स्वागत करता है।

इस मई दिवस पर सीटू–

❖ अपने इस विश्वास को दोहराता है कि आज देश के मजदूर वर्ग तथा शोषित–पीड़ित जनता के समक्ष जो चुनौतियां दरपेश हैं, वे तितरफा संघर्ष–नव–उदारवाद के खिलाफ संघर्ष, विभाजनकारी सांप्रदायिक तथा जातिवादी ताकतों के खिलाफ संघर्श और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष–की जरूरत पेश करती हैं।

❖ सीटू इस मई दिवस पर इन तीनों चुनौतियों का प्रभावी ढ़ंग से सामना करने के लिए देश में पूरे मजदूर वर्ग को लामबंद करने के अपने दृढ़ निश्चय की घोषणा करता है।

❖ सीटू इस मई दिवस पर संयुक्त संघर्ष के मंच पर शोषित–पीड़ित जनता के तमाम तबकों की एकता को मजबूत करने तथा व्यापक बनाने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराता है। जनविरोधी सामाजिक–आर्थिक तथा सामाजिक निजाम के प्रतिरोध के लिए संघर्ष को बुलंदियों तक ले जाने की यह पूर्व शर्त है।

❖ सीटू इस मई दिवस पर अपने इस विश्वास को दोहराता है कि बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता तथा तत्ववाद एक दूसरे के आधार पर ही फलते–फूलते हैं। हर रंगत तथा झंडों की सांप्रदायिकता जनता को विभाजित करती है, उनकी एकता को भंग करती है, रोजमर्रा के वास्तविक मुद्दों ध्यान हटाती है, असली अपराधियों–नव उदारवादी नीतियों तथा शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ उनके संघर्ष को कमजोर करती है और अंततः सांप्रदायिकता शोषणकारी वर्गों के ही हित साधती है।

❖ सीटू इस मई दिवस पर नव–उदारवादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था जो शोषण को तेज करने के लिए मजदूरों, गरीब किसानों तथा खेतमजदूरों को सभी को गुलाम बनाती है, के खिलाफ लडने के लिए उनकी एकता की जरूरत पर जोर देता है और इस दिशा में काम करने का संकल्प लेता है।

❖ सीटू इस मई दिवस पर शोषित–पीड़ित जनता की व्यापकतम संभव लामबंदी को हासिल करने के लिए नव–उदारवाद की ठोस वैकल्पिक नीतियाँ पेश करने के जरिए स्वतंत्र अभियान चलाने, संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन और साथ ही साथ सभी शोषित–पीड़ित जनता के एकजुट संघर्षों को मजबूत करने की पहलकदमी करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

❖ सीटू इस मई दिवस पर अपने इस विश्वास को दोहराता है कि केवल इस तरह के जबर्दस्त संघर्षों का विकास ही वर्गीय शक्तियों के संतुलन को मजदूर वर्ग के पक्ष में व्यापक रूप से बदलने की ओर ले जा सकता है।

वर्ष 2018 के इस मई दिवस पर सीटू भारत के मजदूर वर्ग से यह अपील करता है कि–

✓ नव–उदारवाद की नीतियों को मात देने के लिए और मजदूरपरस्त तथा जनपरस्त वैकल्पिक नीतियों के लिए एकता को मजबूत करे तथा संघर्ष को तेज करे।

✓ एकता को भंग करनेवाली सांप्रदायिक तथा जातिवादी ताकतों की साजिशों के प्रति सतर्क रहे और उन्हें मात दे।

✓ शोषित–पीड़ित जनता के तमाम तबकों–मजदूरों, खेतमजदूरों तथा गरीब किसानों आदि के बीच एकजुटता के बंधनों को और मजबूत करे।

✓ मजदूर वर्ग तथा शोषित–पीड़ित जनता के तमाम तबकों के असली शत्रुओं–पूंजीवादी प्रणाली तथा इस व्यवस्था को आगे बढ़ानेवाली राजनीति तथा ताकतों को पहचाने और इस शोषणकारी व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष की तैयारी करे।

इस मई दिवस पर सीटू, हर तरह के शोषण तथा दमन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकजुटता तथा एकता के समर्थन में अपना झंडा बुलंद करता है।

❖ **पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो!** ❖ **समाजवाद जिंदाबाद!!**

❖दुनिया के मजदूरों एक हो!!!

मई दिवस 2018 पर डब्ल्यू एफ टी यू का आह्वान

मई दिवस 2018 : अंतर्राष्ट्रीयतावाद व एकजुटता के साथ

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (डब्ल्यू एफ टी यू) सारी दुनिया में अपने 9 करोड़ 20 लाख संबद्धों की ओर से, इस महान दिवस के अवसर पर, दुनिया के प्रत्येक हिस्से में रहने, कार्य करने व संघर्ष करने वाले सभी मजदूरों को सलाम करता है। हमारे दुश्मनों के प्रयासों के बावजूद मई दिवस मजदूरों के लिए संघर्षों का प्रकाशपुंज था, है और रहेगा। मई दिवस को, बुर्जुवाजी, साम्राज्यादियों व उनके अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ की नीतियों के विरूद्ध प्रतिरोध का संदेश बने रहना होगा।

इसके साथ ही, 1886 को शिकागो में बहा मजदूरों का खून हमें आज हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है; यह हमें स्मरण कराता है कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता; हमारे वर्ग के द्वारा जीते गये हर अधिकार या आजादी को बलिदानों, द्वद्वों व संगठित संधर्षों के बल पर जीता गया है।

आज जब प्रोद्योगिकी व वैज्ञानिक तरक्की ने सामाजिक संपदा की पैदावार को बढ़ाने में योगदान किया है, हमारे वर्ग के जीवनयापन के हालात बदतर हैं। प्रत्येक पूंजीवादी देश में, मालिक हमारे वर्ग की उपलबधियों पर हमलावर है; वे तनख्वाहों, पेंशन व सामाजिक सुरक्षा को खत्म कर रहे हैं; वे हर एक चीज का निजीकरण कर रहे हैं; वे तो हड़ताल के जैसे पवित्र अधिकार पर हमला बोलने में भी नहीं हिचक रहे ! हड़ताल ही तो हमारे हाथों में सबसे मजबूत हथियार है, और हम किसी को भी इसे संकुचित करने, सीमित करने या समाप्त करने की इजाजत नहीं देंगे।

इसी के साथ, वे व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय युद्दों की तैयारियां व उनका संचालन कर रहे हैं। वे अपने मुनाफों को अधिकतम करने के लिए नये नरसंहारों का रास्ता तैयार करेंगे; राष्ट्रों को तबाह कर देने वाले नये साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों का रास्ता तैयार करेंगे तथा लोगों का खून बहाकर उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित करेंगे। लीबिया व सीरिया में जारी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, वेनेजुएला के विरूद्ध बड़ती आक्रामकता अमेरिका द्वारा येरूशलम को इजराईल की राजधानी के रूप में मान्यता देने, अरब में दखलंदाजी, कोरियाई प्रायद्धीप में तनाव इस बात के संकेत हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों ने मुनाफों के लिए नये क्षेत्रों को निशाने पर ले लिया है; और हर बार मजदूरों की लाशों पर ऐसा होता है।

पूंजीबाद के गहरे आर्थिक संकट तथा नये बाजारों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न साम्राज्यवादी केन्द्रों में तीखी प्रतिद्वंदि की वर्तमान परिस्थितियों में, हमारे सबसे ताकतवर हथियार हैं अंतर्राष्ट्रीयतावाद व एकजुटता। किसी भी मजदूर को अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिये। एक साथ मिलकर हमें एकजुटता व अंतराष्ट्रीयतावाद के साथ कार्ल मार्क्स के कथन ''दुनिया के सर्वहारा एक हो'' को वास्तविकता बनाने के लिए मजदूर वर्ग की एकता के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिये।

इस संदर्भ में, और इस वर्षगांठ पर, वुफ्टू हमारे शोषित, सताये भाईयों के प्रति, प्रवासियों व शरणार्थियों के प्रति जो या तो साम्राज्यवाद की गोलियों के कारण या इस व्यवस्था द्वारा पैदा की गई गरीबी व बदहाली के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने को मजबूर हैं, के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करता है। वुफ्टु उनके पक्ष में बराबर खड़ा रहेगा और एक शोषणविहान व शरणार्थी विहीन दुनिया के लिए लड़ता रहेगा। प्रवासियों को अवश्य ही यूनियनों का अभिन्न अंग होना चाहिये, उन्हें स्थानीय मजदूर के साथ एकजुट हो वेतन व अधिकारों तथा युद्ध व हस्तक्षेपों के विरूद्ध लड़ना चाहिये।

हम, अपना एक जनवादी देश हासिल करने के बहादुर फिलस्तीनी जनता के संधर्श के साथ अपनी आवाज उठाते हैं। इसके साथ ही, हम दोगुने, शोषण का सामना करने वाली संधर्षरत महिला मजदूरों के संधर्षो में उनके साथ है। हाल ही में पनामा में हुई वर्ल्ड वीमेंस काँग्रेस में वुफ्टू की महिला सदस्यों ने पुरजोर घोषणा की कि वे कार्य, समाज व जीवन में बराबर अधिकार चाहती हैं। वुफ्टू भी इस बराबरी के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। इसी उन्मुखता का पालन हम युवा मजदूरों के संदर्भ में भी करते हैं चूंकि मजदूरों की युवा पीढ़ी के रूप में, मई दिवस की संधर्ष की सबसे बेहतर परंपराओं को आगे बढ़ाना उनका काम है।

इस वर्ष को वुफ्टूने, उठ खड़े होने वाले प्रत्येक की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, ट्रेड यूनियन शिक्षण व प्रशिक्षण का वर्ष घोषित किया है। हमारा उद्वेश्य यह है कि मजदूरों की नई पाली दबी न हो जुझारू हो तथा वर्ग समझौते व सहयोग की दुश्मन हो। हम ट्रेड यूनियन शिक्षण वर्ष को मनाते हुए प्रत्येक यूनियन का आहवान करते हैं कि वह मई दिवस के सच्चे अर्थ को व इसके लिए मजदूर वर्ग द्वारा किये गये बलिदान को सामने लाने के लिए जुझारू योगदान करे। हमारे आन्दोलन की याद को संजोते हुए हम

कल के आन्दोलनों के लिए एक विरासत छोड़ रहे हैं और भविष्य के लिए हमारे पास उक औजार भी है। हमारे आन्दोलन के इतिहास को जानना एक कर्तव्य है। वुफ्टू आगे कदम बढ़ाता है, मजबूती हासिल करता व बढ़ता है : और यही हमारे विरोधियों को भयभीत करता है। वुफ्टू की उपस्थिति हर कहीं, दुनिया के हर कोने में दर्ज कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ताकि कहीं भी भूखा, दमित, शाषित मजदूर न हो। वुफ्टू को मनुष्य के शोषण से रहित व्यवस्था के भविष्य के संघर्ष में, संघर्ष का उद्गम बनना होगा। इसी तरह से हम वुफ्टू के प्रथम महासचिव लुई सैलान्ट की 1945 में प्रदान की गई दिशा को वास्तविक कर पायेंगे। वुफ्टू सारी दुनिया के मजदूरों के लिए!

मई दिवस जिन्दाबाद!

कर्नाटक

बी एस एन एल के ठेका मजदूरों का धरना

बी एस एन एल कॉंट्रेक्ट वर्कर्स फेडरेशन (बी एसएनएल सी डब्लू एफ) के आखिल भारतीय आहवान पर बी एस एन एल एन पी डब्लू यू (सीटू) के बैनर तले कर्नाटक के एक हजार से अधिक बी एस एन एल ठेका मजदूरों ने 15 मार्च को बंगलूरू में मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर राज्य स्तरीय धरना दिया। कर्नाटक सर्किल के सभी जिलों से ठेका मजदूर शामिल हुए।
यह आंदोलन, पैसे की अनुपलब्धता के नाम पर छंटनी, न्यूनतम वेतन भुगतान केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुरूप न करने के विरोध में, हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने, बोनस के भुगतान, पहचान पत्र जारी किये जाने, पी एफ अथारिटी के पास ई पी एफ के पैसे की उचित वापसी व जमा, कार्य पर रहने के दौरान मजदूर की मृत्यु हो जाने पर परिवार को मुआवजे के भुगतान, कार्य के लिए सामग्री की उचित आपूर्ति तथा टॉवर कंपनी स्थापित किये जाने का विरोध आदि जैसी माँगों को लेकर किया गया था। धरने का उद्घाटन फेडरेशन के वी ए एन नंबूदिरि ने और संबोधन फेडरेशन के महासचिव अनिमेश मित्रा, बी डब्लू यू के नेताओं ने किया।

एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य महाप्रबंधक से मुलाकात की व माँगों का ज्ञापन सौंपा व उन पर चर्चा की। मुख्य महाप्रबंधक ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ कॉरपोरेट कार्यालय के समक्ष उठाने का भरोसा दिया। प्रबंधक की ओर से जी एस एच आर व जी एम सी एफ ए ने धरना स्थल पर मजदूरों से मुलाकात की तथा प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में प्रबंधन के रूख के बारे में बताया। (योगदान : गुंडन्ना सी के)

श्रमिक और संसदीय जनतंत्र

[बी. आर. अंबेडकर द्वारा 17 सितम्बर, 1943 को दिए भाषण से]

[14 अप्रैल को बी आर अंबेडकर का जन्म दिवस होता है। इस अवसर पर हम उनके द्वारा 17 सितम्बर, 1943 को एक ट्रेड यूनियन मजदूरों के शिक्षण शिविर के समापन के मौके पर दिये भाषण के अंश प्रकाशित कर रहे हैं।]

सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र एक राजनीतिक लोकतंत्र का ताना–बाना होता है..... संसदीय लोकतंत्र स्वतंत्रता के बारे में एक उमंग पैदा करता है। यह समानता के महत्व को समझने में असफल रहा है और इसने स्वतंत्रता व समानता के बीच एक संतुलन बिठाने की कोशिश तक नहीं की है, इसका परिणाम है कि स्वतंत्रता ने समानता को निगल लिया और असमानता की एक संतति को पीछे छोड़ दिया।

सभी राजनीतिक समाज दो वर्गो में बंट गये–शासक और शाषित..... लेकिन इसका दुर्भायपूर्ण अध्याय यह है कि यह विभाजन इतना रूढ़ व स्तरीकृत हो गया कि शासक हमेशा शासक वर्ग से आने लगे और शाषितों का वर्ग कभी शासक वर्ग नहीं बनता। लोग स्वयं पर शासन नहीं करते वे एक सरकार बनाते हैं और उसे अपने ऊपर शासन करने की छूट देते है, यह भूलते हुए कि वह उनकी सरकार नहीं है।

संसदीय जनतंत्र में कभी भी सरकार जनता की व जनता के द्वारा नही रही है और इसलिए यह सरकार कभी भी लोगों के लिए नहीं रही है। संसदीय जनतंत्र, एक लोकप्रिय सरकार के लटके–झटके को छोड़कर, वास्तविकता में एक आनुवांशिक मातहत वर्ग पर एक आनुवांशिक शासक वर्ग की सरकार होती है। राजनीतिक जीवन का यह घनचक्कर संगठन ही संसदीय जनतंत्र को इस कदर असफल बनाता है। इस कारण से ही संसदीय जनतंत्र स्वतंत्रता, संपत्ति व खुशहाली प्रदान करने की जगायी उम्मीद को पूरा नहीं करता है।

प्रश्न है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि संसदीय जनतंत्र गरीबों, श्रमिकों व दबे–कुचले वर्गों को लाभ पहुँचाने में असफल रहा है तो यही वर्ग इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। प्रथम तो उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कारक के प्रभाव को सबसे बुरी तरह से नजरंदाज किया है।

मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया..... यदि यह सिद्धांत पूरी तरह से सत्य नहीं है तो ऐसा इसलिए है कि पूरा श्रमिक, वर्ग आर्थिक तथ्यों को वैसी शक्ति से सामने नहीं रख पाया जैसी जीवन की ऐसोशिएसन को गठित करने में उनकी होती है।

श्रमिक वर्ग अपने आपको मानवजाति की सरकार से संबंधित साहित्य से परिचित कराने में असफल रहा है। श्रमिक वर्ग के हर सदस्य को रूसो के सोशल कॉंट्रेक्ट से, मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणापत्र, श्रमिकों के हालात पर पोप लिओ तेरहवें के एन– साइक्लीकल तथा स्वतंत्रता पर जॉन स्टुअर्ट मिल के लेखन से परिचित होना चाहिये। आधुनिक समय के सामाजिक व सरकार के संगठन के बारे में कम से कम ये चार बुनियादी दस्तावेज हैं। लेकिन श्रमिक वर्ग उन्हें वह तवज्जो नहीं देगा जिसके ये दस्तावेज हकदार हैं। इसके उलट श्रमिक प्राचीन राजाओं व रानियों की झूठी व परीकथाओं को पढ़ने में मजा लेता है और वह उनका लती हो गया है।

एक और बड़ा अपराध है जो उन्होंने अपने साथ किया है वह यह कि उन्होंने सरकार पर कब्जा करने की कोई महत्वकांछा विकसित नहीं की है और वे अपने हितों की हिफाजत करने के लिए सरकार पर कब्जा करने को जरूरी मानने के प्रति आश्वस्त नहीं। वास्तव में तो उनकी सरकार में ही कोई रूचि नहीं है। मानवजाति को जितनी भी विपदाओं का सामना करना पड़ा है यह उनमें सबसे बड़ी व निंदनीय है।

ट्रेड यूनियनें यदि वे ताकतवर भी हों, तो भी वे इतनी ताकतवर नहीं कि पूंजीपतियों को पूंजीवाद को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए मजबूर कर सकें। ट्रेड यूनियनें कहीं ज्यादा प्रभावी होंगी यदि निर्भर करने के लिए उनके पीछे एक श्रमिकों की सरकार हो। सरकार पर कब्जा करना श्रमिकों का अवश्य ही लक्ष्य हो जिसपर उनका निशाना सधा हो।

मजदूर वर्ग, जो हर तरह से कंगाल होता है और जिसके पास देने को फालतू कुछ नहीं होता, अक्सर ही तथा कथित राष्ट्रवाद के लिए अपना सब–कुछ बलिदान कर देता है। उन्होंने कभी यह जानने की परवाह नहीं की कि राष्ट्रवाद जिसके लिए वे अपना सब कुछ देरहे हैं, जब स्थापित हो जायेगा तो क्या वह उन्हें सामाजिक व आर्थिक बराबरी देगा।

अक्सर ही एक सफल राष्ट्रवाद से उभरा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य जो उनके बलिदान की देन होता है, अपने आकाओं के दबदबे के नीचे मजदूर वर्ग का दुश्मन बन जाता है। यह शोषण का सबसे बुरा रूप है जिसे श्रमिकों ने अपने ऊपर होने की इजाजत दी है।

यदि मजदूर वर्ग को एक संसदीय जनतंत्र की व्यवस्था के तहत रहना है तो उन्हें इसे फायदे के औजार में बदलने के लिए, सबसे अच्छे संभव उपाय करने होंगे। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली तो यह कि केवल ट्रेड यूनियन स्थापित करने को ही अंतिम लक्ष्य व उद्देश्य मानने की धारणा को त्यागना होगा। उन्हें अवश्य ही यह धोषित करना होगा कि उनका लक्ष्य श्रमिकों को सरकार की बागडोर सौंपना है। और इसके लिए उन्हें अवश्य ही एक श्रमिक पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित करना चाहिये..... उन्हें अवश्य ही अपने आपको हिन्दू महासभा या काँग्रेस जैसी पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों से अलग करना चाहिये..... श्रमिकों के एक अलग राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित होने से दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वे अपने आपको काँग्रेस व हिन्दू महासभा के शिकंजे से मुक्त कर भारत की आजादी की लड़ाई कहीं बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। इससे वे राष्ट्रवाद के नाम पर अपने आपको ठगे जाने से भी बचा सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इससे भारतीय राजनीति में कुर्तक या अविवेक पर ताकतवर लगाम लग जायेगी..... दूसरी बात जिसे भारतीय श्रमिकों को समझना है वह यह कि बिना ज्ञान के सत्ता या ताकत नहीं मिल सकती है..... यह भी नहीं भूलना चाहिये कि एक श्रमिक सरकार का रास्ता अन्य वर्गो की सरकारों से कठिन व भिन्न होगा। श्रमिकों की सरकार अहस्तक्षेप की सरकार नहीं हो सकती है। यह एक ऐसी सरकार होगी जो अवश्य ही नियंत्रण की व्यवस्था पर आधारित होगी। एक नियन्त्रण की व्यवस्था के लिए एक अहस्तक्षेप वाली सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से भारत में श्रमिकों ने अध्ययन के महत्व को महसूस नहीं किया है। भारत में श्रमिक नेताओं ने जो किया है वह यह कि वे उद्योगपतियों को कितने बेहतर ढंग से गाली दे सकते हैं। गाली देना और गाली देना ही जैसे श्रमिक नेता की भूमिका का आदि व अंत है।

सी बी टी के फैसलों के उल्लंघन का सीटू ने विरोध किया

13 मार्च, 2018 को सीटू महासचिव तपन सेन ने एम्पलाईज डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ई डी एल आइ) के संबंध में सी बी टी के फैसलों के उल्लंधन के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोश गंगवार को पत्र लिखा।

सी बी टी के सर्वसम्मत फैसले थे–(1) सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु होने पर ई डी एल आइ स्कीम के तहत 2.5 लाख रूपये का न्यूनतम आश्वस्त लाभ व (2) रू० 30,000, रू० 40,000 व रू० 50,000 के औसत मासिक वेतन स्तर के आधार पर एक ग्रेडेड तरीके से 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को एक लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट।

तथापि, 21 फरवरी की एक ई पी एफ ओ विज्ञाप्ति तथा स्कीम को संशोधित करते हुए 15 फरवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं जी एस आर 170 (ई) के द्वारा; सरकार ने फैसलों को आंशिक रूप से ही लागू किया वह भी विलंब के बाद। ई पी एफ ओ ने त्रिपक्षीय के फैसलों के ऐसे घोर उल्लंधन पर कोई सफाई नहीं दी। ऐसा उल्लंधन कर्मचारियों को मिलने वाले वैध लाभों से उनको वंचित करता है बल्कि इससे वैधानिक त्रिपक्षीय मंच की साख को बट्टा लगता है, तपन सेन ने लिखा।

सीटू ने कड़ा विरोध करते हुए माँग की कि ई डी एल आई स्कीम के तहत ''लॉयल्टी कम लाईफ'' बेनिफिट को, जैसा कि सी बी टी ने सर्वसम्मति से तय किया, अविलम्ब लागू किया जाये और इस बारे में अलग अधिसूचना जारी की जाये।

रोजगार सृजन के बारे में मोदी सरकार की झूठी व भ्रामक बयानबाजी

जे एस मजुमदार

वर्ष 2018–19 के अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने रोजगार सृजन के बारे में एक झूठा व एक भ्रामक बयान दिया। अपने लिखित भाषण की बिन्दु संख्या 78 में मंत्री ने कहा कि ''हाल ही में किये गये एक स्वतन्त्र अध्ययन ने यह दिखाया है कि इस वर्ष 70 लाख औपचारिक रोजगारों का सृजन होगा'' (वित्तीय वर्ष–18) (बल देने हेतु रेखांकित)।

बजट भाषण में जेटली का झूठा बयान

'स्वतन्त्र अध्ययन' का जेटली का उपरोक्त बयान झूठा था। दरअसल यह अध्ययन प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी से उसके दिशा निर्देशन में इसकी रूपरेखा बनाकर शुरू किया गया था। घटते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी के अपने ही आंकड़ो से त्रस्त मोदी सरकार ने जो इस निराशाजनक तस्वीर से बाहर निकलने या बचने को बेताब थी जिसमें श्रम ब्यूरो ने बताया था कि दिसम्बर 2016 तक के 9 महीनों में आठ श्रम आधारित सैक्टरों में मात्र 2.31 लाख रोजगार पैदा किये जा सके थे और बढ़ती बेरोजगारी की दर 5 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2016–17 के आर्थिक सर्वेक्षण में श्रम ब्यूरो के हवाले से कहा गया था कि ''रोजगार वृद्धि सुस्त रही'' है। इस वास्तविकता को छिपाने के लिए मोदी सरकार को एक ''स्वतंत्र'' अध्ययन की जरूरत थी। केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने 3 अगस्त , 2016 को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा था कि ''पिछले तीन वर्षों में जी डी पी में 6–7 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद महत्वपूर्ण श्रम सधन व निर्यातोन्मुख क्षेत्रों ने रोजगार वृद्धि के बारे में मंदी के संकेत दिये हैं।''

ठीक इसी प्रकार अरूण जेटली के बजट भाषण में रोजगार के बारे में श्रम ब्यूरो के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2018 में ''70 लाख औपचारिक रोजगार'' पैदा करने के दावे के बाद मंत्री का कहना था कि तीन वर्षों के दौरान हमने देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं' और कि ''इन कदमों ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिये हैं।''

प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री के द्वारा दावा किये जाने वाला यह अध्ययन कितना ''स्वतंत्र'' था ? बिजनेस स्टैंडर्ड ने 16 फरवरी को अपनी खबर में बताया कि 29 अक्टूबर, 2017 को पी एम ओ ने नीति आयोग को कहा कि ''रोजगार के संदर्भ में वांछित प्रवृत्तियां ''दिखाने में सक्षम बनाने के लिए वह जल्द से जल्द'' रोजगार के आंकड़ो पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकेतकों का जुगाड़ करे।

पी एम ओ के निर्देशानुसार ने कर्मचारि भविष्य निधि (ई पी एफ) के ग्राहकों के बारे में वित्तीय वर्ष 2018 के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग ने ई पी एफ ओ को 2017 के अप्रैल से अक्टूबर तक के समय का ई पी एफ ओ के ग्राहकों का आंकड़ा प्रदान करने को कहा। इसी के अनुरूप ई पीं एफ ओ ने हैदराबाद के अपने राष्ट्रीय डाटा केन्द्र से नीति आयोग को ई पी एफ के 8.7 करोड़ सदस्यों का एन्क्रिप्ट्ड डाटा उपलब्ध कराया। इसके बाद नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस डाटा को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग के कार्यालय में बैठे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइ आइ एम) बैंगलोर के पुलक घोष और भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्या कान्ति घोष को उपलब्ध कराया, जैसा कि नीति आयोग का निर्देश था।

यहाँ तक कि इस तथाकथित स्वतंत्र अध्ययन के लिए समय निर्धारण भी पी एम ओ ने किया था। पी एम ओ ने 29 अक्टूबर, 2017 को नीति आयोग को मुख्यतः ई पी एफ ओ के आंकड़ो के आधार पर इस ''स्वतंत्र अध्ययन'' को तैयार करने का निर्देश दिया था। इसी के अनुरूप नीति आयोग ने 2 नवम्बर को ई पी एफ ओ को लिखा; ई पी एफ ओ ने 4 व 27 नवम्बर को नीति आयोग को आँकड़े उपलब्ध कराये; आई आई एम व एस बी आइ के घोषों को दिल्ली लाकर नीति आयोग के कार्यालय में उनके ''स्वतंत्र अध्ययन'' की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिठाया गया जिसे 12 जनवरी, 2018 को उन्होंने पी एम ओ को प्रस्तुत किया और पी एम ओ ने रिपोर्ट को मंजूरी दे दी; फिर इस रिपोर्ट को 16 जनवरी को प्रसारित एक विशेष साक्षात्मक में रिपोर्ट का हवाला दिया और अन्ततः

वित्तमंत्री ने 1 फरवरी, 2018 को अपने बजट भाषण में इस रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018 में 70 लाख रोजगार पैदा होने का दावा किया।

यह ''स्वतंत्र अध्ययन'' आइ आइ एम, बैंगलोर व 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' द्वारा किये गये एक अध्ययन के रूप में प्रकाशित हुआ। जैसा कि पी एम ओ ने चाहा था आइ आइ एम के घोष व एस बी आइ ने घोष के अपनी रिपोर्ट में कहा ''भारत में रोजगार को मापने वाले ज्यादातर सर्वेक्षण भ्रामक होते हैं'' और श्रम ब्यूरो के ''सर्वे की भी कई सारी सीमायें हैं।''

जेटली का भ्रामक बयान

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के रूप में यह कहा गया है कि ''सभी अनुमानों के आधार पर मौजूदा राजकोष में हर महीने 5.9 लाख (अर्थात प्रतिवर्ष 70 लाख) पे रोल बनते हैं।'' इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 में कुल 70,4 लाख पे रोल एनरोल हुए हैं जिनमें 190 उद्योगों (प्रत्येक संस्थान में कार्यरत लोग 20 से अधिक) में कार्यरत 55.2 लाख ई पी एफ सदस्य और 65 उद्योगों में (प्रत्येक में कार्यरत लोग 10 से अधिक) कार्य अनुमानित 8.8 लाख गैर बीमित, गैर ई पी एफ, ई एस आइ सी आइ पी' लोग और केन्द्र तथा राज्य सरकारों में 2004 के बाद शामिल होने वाले 6.4 लाख एन पी एस ग्राहक भी शामिल हैं। ई एस आइ सी श्रेणी के लिए घोष एंड घोष ने ऐसे संस्थानों में 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन लोगों को जो ई पी एफ व ई एस आइ सी दोनों के दायरे में हैं, को बाहर करने के लिए रिपोर्ट में 50 प्रतिशत ''हेयरकट'' (रिपोर्ट में स्वयं उन्होंने ही इस भाषा का प्रयोग किया है) किया। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह रिपोर्ट में इस ई पी एफ–ई एस आइ सी तथा एन पी एस अनुच्छेद को ''संगठित'' या ''औपचारिक'' क्षेत्र के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। इस औपचारिक क्षेत्र में स्थायी व ठेका कर्मचारियों की व्यापक संख्या, दोनों ही को शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ''इस स्वतंत्र अध्ययन'' का प्रयोग बड़ा आसानी से ''औपचारिक क्षेत्र'' को ''औपचारिक रोजगार;; (स्थायी रोजगार) से और ''पे रोल सृजन'' को ''रोजगार सृजन'' के साथ बदलने के लिए किया।

आई आई एम व एस बी आई के घोषों की यह रिपोर्ट अपने निष्कर्ष में भ्रामक है। उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की है कि ''पे रोल एनरोलमेंट'' का भारी बहुमत उस ''रिप्लेसमेंट एम्पलॉयमेंट'' का था जो आइ टी और आइ टी एस उद्योगों समेत संगठित क्षेत्र में घर्षण की ऊंची दर और रोजगार की ''नेचुरल वेस्टेज'' (स्वाभाविक बर्बादी) के चलते हुआ।

बहरहाल, इस अध्ययन क`लेखकों ने कभी भी ''रोजगार सृजन'' का दावा नहीं किया। उनका निष्कर्ष ''पे रोल के सृजन'' का था जो ई पी एफ, एन पी एस तथा ई एस आइ सी के आंकडों में प्रतिबिंबित होता है।

व्यक्तिगत डाटा की अनधिकृत डिकोडिंग

आधार व फेसबुक आदि के डाटा की डिकोंडिंग तथा उसके दुरूपयोग के बारे में चल रही गरम बहस के बीच यहसवाल उठता है कि ई पी एफ सदस्यों के व्यक्गित डाटा को अनधिकृत लोगों को कैसे दिया गया। ऐसा हैकिंग के कारण नहीं था बल्कि यह डाटा रखने वालों का एक सोचा–समझा कृत्य था।

यहाँ तक कि कर्मचारियों के नामों, उनकी जन्म तिथियों, स्थायी खाता नंबरों, पी एफ व उद्योग के नामों आदि सहित ई पी एस के 8.7 करोड़ सदस्यों का यह भारी भरकम डाटा किसलिए माँगा जा रहा है, इस बारे में नीति आयोग ने ई पी एफ ओ को भी अंधेरे में रखा। ई पी एफ ओ ने सारे डाटा बेस को एक फाईल सर्वर पर रखा और एफ यू आर एल प्रदान करा दिया, जिसे कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, बस इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास सर्वर का लिंक होना चाहिये। घोष एंड घोष के द्वारा ई पी एफ ओ के सदस्यों के डाटा को प्रयोग में लिए जाने के बाद इस यू आर एल को हटा दिया गया।

ई पी एफ ओ का गठन संसद के एक विशेष कानून के जरिये किया गया है। ई पी एफ ओ एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज प्रमुख है। जब 21 फरवरी, 2018 को हुई सी बी टी बैठक में, सीटू के प्रतिनिधि और उसके राष्ट्रीय उपाध यक्ष ए के पद्मनाभन ने यह पूछा कि निजी शोधकर्ताओं को ई पी एफ ओ का डाटा कैसे दिया गया तो सी बी टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय श्रम मंत्री के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

उद्योग व क्षेत्र

इस्पात

''वाइज़ेग स्टील मार्च''

उमड़ा लाल सैलाब

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर आइ एन एल) के वाइजेग स्टील प्लांट (वी एस पी) जो लौह अयस्क की गंभीर कमी का सामना कर रहा है जिससे वी एस पी को भारी नुकयाान हो रहा है, के लिए बंधक लौह अयस्क खदान के आवंटन; विस्थापित लोगों के लिए रोजगार की माँग; तथा आर आइ एन एल के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करते हुए हजारों कर्मचारी व उनके परिवार 5 अप्रैल को सीटू की स्टील प्लांट एम्पलाईज यूनियन (एस पी ई यू) द्वारा आयोजित स्टील प्लांट से सिटी सेंट्रल पार्क तक के 26 किलोमीटर लंबे ''वाइजेग स्टील मार्च'' में शामिल हुए।

सुबह 5:30 बजे बी आर अंबेडकर व ज्योतिबा फुले की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद एस पी ई यू के अध्यक्ष सी एच नरसिंगराव ने मार्च को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मार्च में वी एस पी के लगभग 2500 कर्मचारी व उनके परिवार शामिल थे। गाजुवाका क्रॉसिंग पर और 1000 कर्मचारी इसमें जुड़े तथा सुबह 9 बजे एन ए डी क्रॉसिंग पर अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लगभग 2000 कर्मचारी स्टील मार्च में शामिल हो गये तब मार्च 14 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुका था।

वी एस पी के लिए बंधक खदान न्यायोचित

वाइजेग स्टील प्लांट (वी एस पी) सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील संयन्त्रों में अकेला है जिसे कोई बंधक लौह अयस्क खदान आवंटित नहीं है। इसकी उत्पादन लागत बंधक खदान वाले संयन्त्रों से 30 प्रतिशत ज्यादा है

यह नवरत्न स्टील प्लांट एन एम डी सी द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले लौहे अयस्क पर चलता है। पिछले वर्ष एन एम डी सी ने 6.5 एम टी लौहे अयस्क की आपूर्ति अपनी छत्तीसगढ़ की डोनीमलाई खदानों से पिट हेड पर 2100 रूपये प्रति टन की दर से की। वी एस पी को रू० 1200–1300 परिवहन तथा रू० 600 रॉयल्टी पर देकर कारखाने तक लाने में हर टन पर करीब रू० 4000 रूपये खर्च करने पड़े। संसद में हुई चर्चा में यह सामने आया कि यदि वी एस पी के पास बंधक खदान होती तो यह लागत केवल लगभग रू० 500 प्रति टन आती। यदि इसकी बंधक खदान ओडिशा में होती जो वाइजेग से नजदीक है तो परिवहन का खर्च और भी कम पड़ता।

स्टील की माँग कम रहने से वी एस पी स्टील के दाम नीचे रहे और उसे प्रतिटन स्टील पर लगभग 1000 रूपये गंवाने पड़े। वी उस पी जिसने 7.3 मिलियन टन के उत्पादन तक पहुँचने के लिए आधुनिकीकरण पर 4000 करोड़ रूपये निवेश किये हैं, उसे वर्ष 2016–17 में रू० 1200 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब वी एस पी को 15 वर्ष तक लगातार मुनाफे के बाद घाटा हुआ है। *(बिजनेस स्टैंडर्ड : 6 अगस्त 2017)*

वहाँ से लेकर यह मार्च लहराते लाल झंडो पताकाओं के उमड़ते समुद्र जैसा था; लोगों ने घरों व दुकानों से निकलकर अभिनंदन किया; लोग फ्लाइओवरों व छतों पर खड़े होकर देख रहे थे। रास्ते में 22 जगहों पर विभिन्न ट्रेड यूनियनों व अन्य जनसंगठनों द्वारा मार्च का स्वागत किया गया।

दोपहर 12 बजे तक सिटी सेंटर पार्क के नजदीक पहुँचने पर मार्च एक रैली व जन सभा में बदल गया। जन सभा को संबोधित करते हुए सीटू राज्य महासचिव एम ए गफूर ने प्रभावी मार्च के लिए वी एस पी कर्मचारियों को बधाई ई और उनसे आन्दोलन को

वी एस पी के लिए बंधक खदान लेकर जीत हासिल करने और विनिवेश के कदम को परास्त करने तक आगे ले जाने का आहवान किया। मार्च का आयोजन एस पी ई यू ने सीटू की वाइजेग सिटी कमेटी व पी एस यू कोर्डिनेशन कमेटी के साथ समन्वय से किया था। मार्च ने कर्मचारियों में विशेषकर नये भर्ती हुए कर्मचारियों में जोश का संचार किया। तैयारी अभियान के लिए एस पी ई यू ने भारी संख्या में पोस्टर व परचे निकाले; शॉप फ्लोर तक जाकर विभागीय समिति बैठके कीं; विभागीय समितियों ने 'मार्च में भाग लेने की सहमति' पर कर्मचारियों के हस्ताक्षर जमा किये; 30 मार्च को आर आइ एन एल के शहीद केन्द्र पर भारत सरकार के पूर्व सचिव (उर्जा) ई ए एस सरमा द्वारा एक शपथ लो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 19 मार्च को प्लांट से 10 किलोमीटर तक ''वॉक फॉर माईन्स'' का आयोजन एस पी ई यू नेताओं ने किया। स्टील प्लांट की टाऊनशिप व अन्य जगहों पर 2 अप्रैल को पदयात्रायें की गयीं। पी एस यू समन्वय समिति ने मार्च के समर्थन में पुराने गाजुवाका क्रॉसिंग पर एक जन सभा आयोजित की।

बिजली

बिजली के निजीकरण के खिलाफ

उत्तरप्रदेश में बिजली मजदूरों व इंजीनियरों की बड़ी जीत

उत्तरप्रदेश में भाजपा की योगी सरकार ने प्रदेश के सात जिलों–इटावा, कन्नौज, उरई, रायबरेली, सहारनपुर, मऊ व बलिया में बिजली आपूर्ति का निजीकरण करने की अधिसूचना जारी कर निविदायें आमंत्रित की। योगी सरकार ने पाँच शहरों–लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ व मुरादाबाद में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों (डिस्कॉम) की फ्रेंचाइजी का माध्यम से निजीकरण करने की अधिसूचना भी जारी की है।

योगी सरकार के निजीकरण करने के इन कदमों का विरोध करते हुए, बिजली यूनियनों व एसोसिएशनों के संयुक्त मंच, बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों ने सयुक्त रूप से सफल राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जिसमें 14 मार्च को प्रदर्शन, धरने व राज्य स्तरीय विरोध रैली, 27 मार्च को 'काम का बहिष्कार तथा 28 मार्च से वर्क टू रूल तथा 9 अप्रैल से तीन दिन की हड़ताल की सूचना देना शामिल रहा।

5 अप्रैल तक योगी सरकार पीछे हट गयी और राज्य के बिजली मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने संघर्ष समिति को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। लम्बी चर्चा के बाद मंत्री की उपस्थिति में बिजली कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति व प्रमुख सचिव (ऊर्जा) व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की उत्तरप्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि० (यू पी सी एल) के चेयरमैन के बीच लिखित समझौता हुआ कि (i) सात जिलों में निजीकरण के टेंडरों को वापस लिया जायेगा; (ii) बिजली वितरण में कोई भी सुधार उत्तरप्रदेश में बिजली वितरण निगम के मौजूदा तंत्र के तहत और कर्मचारियों व इंजीनियरों को विश्वास में लेकर ही किया जायेगा; (iii) और यह कि ''कर्मचारियों व इंजीनियरों को विश्वास में लिए बिना किसी भी जगह जिनीकरण नहीं किया जायेगा; (iv) अन्य मांगों पर द्विपक्षीय चर्चा कर समाधान किया जायेगा और (v) मौजूदा आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी व इंजीनियर के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

सीटू ने एक बयान जारी कर, सात जिलों में निजीकरण के टेंडर जारी करने के फैसले को वापस लेने के लिए योगी सरकार को मजबूर करने; पाँच शहरों में बिजली वितरण को पूरी तरह निजी हाथों में सौपने के कदम को वापस लेने; बिजली आपूर्ति व वितरण को मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम के तंत्र के तहत जारी रखने तथा योगी सरकार से किसी भी जगह बिजली का निजीकरण न करने की अंडरटेकिग लेकर संयुक्त आंदोलन में बड़ी जीत हासिल करने के लिए उत्तरप्रदेश के बिजलीकर्मियों व इंजीनियरों को बधाई दी।

उत्तरप्रदेश में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की यह जीत नेशनल कोर्डिनशेन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले जारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है जिसने 3 अप्रैल को संसद पर एक विशाल रैली की तथा मोदी सरकार द्वारा संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 को पेश किये जाने वाले दिन एक दिन की हड़ताल की सूचना दी।

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 बिजली वितरण को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव करता है– (i) 'कैरिज' या बिजली वितरण का आधरभूत ढांचा जो प्रमुख रूप से डिस्कॉम या उनकी फ्रेंचाइजीस के पास रहेगा; और (ii) 'कंटेंट' एक विशेष क्षेत्र में 'ओपन एक्सेस' व्यवस्था के माध्यम से कई सारे निजी आपूर्तिकर्ताओं के पास होगा।

विधेयक के संसद में पेश होने से पहले ही, योगी सरकार ने इसे उत्तरप्रदेश में शुरू करने की कोशिश की ओर कंटेट पार्ट के लिए निजी खिलाड़ियों से निविदायें आमंत्रित की जिन्हें नये बिजली कनेक्शन, मीटर लगाने, मीटर रीडिंग, मीटर बदलने, बिल देने, राजस्व जमा करने आदि की उपभोक्ताओं से जुड़ी गतिविधियां चलाने के लिए इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइंडर्स (आइ एस पी) कहा जाना था।

ओडिशा

ओडिशा में बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों का विधान सभा मार्च

ई ई एफ आइ के करीब 3,500 सदस्यों समेत ओडिशा के लगभग 6000 बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों न, ओडिशा बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों के संयुक्त मंच के तहत 14 मार्च को भुवनेश्वर में विधान सभा मार्च किया, विधान सभा पर धरना दिया और रैली व जनसभा की। वे बिजली वितरण को अलग करने, आपूर्ति के निजीकरण व क्रास सब्सिडी को समाप्त करने का प्रस्ताव करने वाले बिजली संशोधन विधेयक 2014 के विरोध तथा एन सी सी ओ ई ई के राष्ट्रीय संयुक्त मंच के आहवान पर हड़ताल समेत बिजली कर्मियों व इंजीनियरों के अखिल भारतीय आन्दोलन का समर्थन कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा ई ई एफ आइ , ओडिशा के चेयरमैन विष्णु मोहंती ने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक एक तरह से पॉवर सेक्टर में मुनाफों के निजीकरण व घाटे के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव कर रहा है।

मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में विधेयक का विरोध करने के लिए राज्य सरकार के हस्तक्षेप; निजी वितरण कंपनियों व, फ्रेंचाइजी के निष्पादन के आकलन के लिए आयोग गठित करने, उनकी असफलता के कारणों की पड़ताल तथा ओडिशा इलैक्ट्रीसिटी रिर्फाम एक्ट, 1995 की समीक्षा की माँग की गई। बिजली का निजीकरण करने वाला ओडिशा पहला राज्य था लेकिन दो दशक बाद भी वह घोषित उद्देश्य को पाने में बुरी तरह से असफल रहा है। ज्ञापन की 16 सूत्री माँगों में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों व अन्य कर्मचारियों से संबंधित मांगें भी शामिल थीं। (योगदान : प्रणय कुमार नायक)

सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के देशभर के 350 से ज्यादा प्रतिनिधि संबंधता से परे जाकर 8 अप्रैल को एरनाकुलम में हुए एक संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में मिले। सीटू महासचिव तपन सेन ने इसकी भूमिका संबंधी परचा कन्वेंशन में पेश करते हुए मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र व मजदूरों की जीविका पर हमले के माध्यम से हो रहे चौतरफा हमले को स्पष्ट किया। इंटक उपाध्यक्ष आर. चंद्रशेखरन, एटक के एच महादेवन, एच एम एस के थंपन थामस, एल पी एफ के कृष्णा, जे ए एफ बंगलुरू के मीनाक्षी सुंदरम तथा पी एस यू सी सी हैदराबाद के वेंकटाचार्य ने समर्थन करते हुए अपने विचार रखे। 30 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।

कन्वेंशन के समापन से पहले सीटू के राष्ट्रीय सचिव एस देवरॉय ने एरनाकुलम धोषणा–पत्र पेश किया जिसमें–(1) 7–11 मई 2018 तक एक सप्ताह लम्बे अभियान के सभी सी पी एस यू में विशाल प्रदर्शनों के साथ समापन तथा प्रधानमंत्री व भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम विभाग मंत्री को यह कहते हुए कि ; ''हम पी एस यू के निजीकरण का कड़ा विरोध करते हैं; हम तय अवधि रोजगार का विरोध करते हैं तथा राजपत्र अधिसूचना को वापस लेने की माँग करते हैं; हम सी पी एस यू में वेतन पुनर्निधारण प्रक्रिया व कंटेंट विशेषकर वहनीयता की शर्त तथा वेज समझौते की तीन वर्षीय समीक्षा के निर्देश पर सभी शर्तो/पाबंदियों को हटाये जाने की मांग करते हैं,'' और (2) उपरोक्त मुद्दों पर 25 मई, 2018 को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का कन्वेंशन करने तथा भविष्य का कार्यक्रम तय करने का प्रस्ताव किया। कन्वेंशन ने सर्वसम्मति से घोषणापत्र को पारित किया।

सी पी एस यू (सीटू) की समन्वय समिति की बैठक

संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन से पूर्व सी पी एस यू की ट्रेड यूनियनों (सीटू) की अखिल भारतीय समन्वय समिति की एक बैठक 7 अप्रैल को एरनाकुलम में हुई जिसमें सारे भारत से सी पी एस यू यूनियनों के 154 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में दो परचे प्रस्तुत किये गये। एक सी पी एस यू के सधन निजीकरण के साथ रोजगार सुरक्षा, पारिश्रमिक व उनके हकों पर हमलों सहित मजदूरों पर मोदी सरकार के चौतरफा हमलों पर था और दूसरा हमलों का प्रतिरोध करने के लिए सीटू के संगठन को मजबूत करने पर था। 23 प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा में भाग लेने के बाद दोनों परचों को सुझावों व कार्यो के साथ सर्वसम्मति से पारित किया गया।

तय अवधि रोजगार का विरोध

पंजाब

स्थायी मजदूरों व स्थायी रोजगार को तय समयावधि के रोजगार के साथ बदलने की मोदी सरकार की अधिसूचना का विरोध करने व मजदूरों की आम हड़ताल के साथ एकजुटता प्रकट करने के सीटू की जनरल कौंसिल बैठक के आहवान पर 2 अप्रैल को लुधियाना में मजदूरों ने रैली व जनसभा कर अपना विरोध व मजदूरों की कार्रवाई के साथ एकजुटता प्रकट की।

पश्चिम बंगाल

सीटू, इंटक, एटक, टी यू सी सी, यू टी यू सी, एच एम एस, एक्टू, ए आइ यू टी यू सी तथा फैडरेशनों– बेफी, एफ एम आर ए आइ, मर्केन्टाइल फेडरेशन व बी एस एन एल के हजारों मजदूरों ने, केन्द्र सरकार द्वारा स्थायी रोजगार के साथ पर तय अवधि रोजगार की शुरूआत करने संबंधी 16 मार्च को जारी अधिसूचना के विरोध में व उसे वापस लिए जाने की माँग करते हुए 2 अप्रैल को कोलकाता में आर एल सी (सी) के सामने प्रदर्शन किया। जन सभा को सीटू के राज्य महासचिव अनादि साहू, इंटक के रामेन पांडे, एटक के उज्जल चौधरी, टी यू सी सी के देबाष चटर्जी यू टी यू सी के दीपक साहा, एक्टू के बासुदेव बसु, ए आइ यू टी यू सी के दिलीप मुखर्जी तथा एच एस एम के बी सी पॉल ने संबोधित किया। सीटू के राष्ट्रीय नेता श्यामल चक्रवर्ती व दीपक दास गुप्ता भी उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता सीटू राज्याध्यक्ष सुभाष मुखर्जी ने की। एक प्रतिनिधिमंडल ने आर एल सी (सी) को ज्ञापन दिया।

किसान आंदोलन

हिमाचल प्रदेश में किया विधान सभा का घेराव

किसान आंदोलन का लाँग मार्च राजस्थान से महाराष्ट्र वाया उत्तरप्रदेश 3 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश पहुँच गया जब राज्य के विभिन्न हिस्सों से आये हजारों किसानों ने केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्ज माफी व लाभकारी मूल्य की राष्ट्रव्यापी साझी माँगों तथा किसानों की बेदखली, दूध का न्यूनतम समर्थन मुल्य 30 रूपये/लीटर, मनरेगा मजदूर को 225 रूपये दिहाड़ी व अभी के 36 दिन के काम के बजाय पूरा काम तथा फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले आवारा पशुओं व अन्य जानवरों की आफत को समाप्त करने की राज्य स्तरीय माँगों को उठाते हुए शिमला में मार्च करते हुए विधान सभा का घेराव किया।

जमीन व किसानों की बेदखली राज्य में गंभीर मुद्दे बन गये हैं। राजस्व अधिनियम में संशोधन के बाद 1,67,399 किसानों ने वन भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदन करते हुए शपथ पत्र भरे हैं। हालांकि, उनमें से अधिकांश हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रीमाइसेज एंड लैंड (एविक्शन एंड टीनेंन्सी रिकवरी) एक्ट 1971 के तहत बेदखली का सामना कर रहे हैं। रैली ने छोटे व सीमान्त किसानों के लिए पाँच एकड़ भूमि दिये जाने की माँग भी उठायी। इस मार्च, रैली व घेराव का आयोजन सी पी आइ (एम) विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में ए आइ के एस की एच पी किसान सभा व एच पी सेब उत्पादक संघ ने संयुक्त रूप से किया था। हजारों किसानों ने पंचायत भवन से मार्च शुरू किया, कार्ट रोड पर विरोध रैली की तथा घंटो तक विधान सभा का घेराव किया जिससे आवागमन ठप्प हो गया।

रैली को संबोधित करते हुए ए आइ के एस राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉ० बीजू कृष्णन ने किसानों की बदहाली के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इनमें नई वन नीति, ठेका खेती व टीनेंसी एक्ट में संशोधन से मुश्किलें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 11 बड़ी बीमा कंपनीयों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक का फायदा पहुँचा है जैसा कि कैंग रिपोर्ट में कहा गया है। उन्होंने किसानों से ए आईके एस 9 अगस्त के राष्ट्रव्यापी जेल भरो व कई राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रमों के बाद 5 सितम्बर को दिल्ली में होने वाली विशाल लामबंदी में शामिल होने का आहवान किया।

किसानों को संबोधित करते हुए राकेश सिंघा ने वन विभाग के द्वारा कब्जे वाली भूमि से किसानों की बेदखली के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि 2014 के आम चुनाव में किसानों से किये वादों को पूरा करने के स्थान पर भाजपा जाति व घर्म के नाम पा लोगों में दरार पैदा कर रही है। सिंघा ने कहा कि राज्य में जमीन नियमित करने के 2000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। आज छोटे व सीमान्त किसान अतिक्रमण हटाने के कोर्ट के आदेश की आड़ में बदेखली का सामना करते संकट में हैं, क्योंकि इसके चलते वे पूरी तरह से भूमिहीन हो रहे हैं। मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। (यू एन आइ व दिब्यून से)

उत्तर प्रदेश में किसानों की रैली

ए आइ के एस के नेतृत्व में राजस्थान व महाराष्ट्र के किसानों के विजयी संधर्षो से प्ररेणा लेकर संगठन की एक अन्य राज्य इकाई, उत्तरप्रदेश किसान सभा ने प्रभावी कर्ज माफी व स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप लाभकारी मुल्य; राज्य में बिजली के बढ़े दामों व उसके निजीकरण को वापस लेने; आवारा पशुओं व जानवरों से फसलों की रक्षा व खेतमजदूरों को 5000 रूपये पेंशन; सभी के लिए प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सामाजिक रूप से हाशिये पर रखे गये दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं पर हमलों को समाप्त करने की माँगो को उठाते हुए 15 मार्च को लखनऊ में 'किसान प्रतिरोध रैली' आयोजित की।

किसान रैली में रूकावट डालने के लिए, चारगाब स्टेशन से जुलूस शुरू करने की मनाही करने व रिफा–ए–आम क्लब में रैली स्थल की मंजूरी को अंतिम समय में रद्द करने वाली योगी सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात किया था। विधान सभा के घेराव की धमकी के बाद ही सरकार ने अलग–थलग पड़े लक्ष्मण मेला मैदान में सभा करने की मंजूरी दी।

लक्ष्मण मंला मैदान में रैली व सभा को किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र के किसान लाँग मार्च के नेता अशोक धवले, महासचिव हन्नान मोल्ला, सी पी आइ (एम) पोलिटब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली व राज्य नेताओं ने संबोधित किया। सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जे एस मजुमदार सीटू के राज्य नेताओ के साथ मजदूरों की एकजुटता प्रकट करने के लिए उपस्थित थे।

उत्तरप्रदेश में मोदी सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी एक छलावा बन कर रह गयी है क्योंकि बहुमत छोटे व सीमांत किसानों को इससे वंचित किया गया है। विभिन्न बहानों व शर्तों के चलते कई लाभान्वितों को तो 1 रूपये व 50 रूपये तक के चेक प्राप्त

हुए हैं। उत्तरप्रदेश सरकार ने 2016 में ही बिजली शुल्क बढ़ा दिया था और अब 7 जिलों में बिजली को निजी हाथों में दिया जा रहा है। न्यूजक्लिक द्वारा उद्घृत किये गये ए आई के एस राज्य सचिव मुकुट सिंह ने बताया कि ''बिजली के बिल 150 गुना तक ऊपर जा चुके हैं।'' (टाईम्स ऑफ इंडिया; न्यूजक्लिक)

राजस्थान के किसानों पर पुलिस कार्रवाई

जयपुर जिले में चोमू के निकट छनवाजी रोड़ पर अवैध टोल नाके को हटाये जाने की माँग करते हुए 22 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत किसानों पर राजस्थान पुलिस ने 1 अप्रैल को लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और रबर की गोलियां दागीं। पुलिस की कार्रवाई तब हुई जब ए आइ के एस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे। कम से कम दर्जन भर किसान घायल हुए। अमराराम को कई अन्य किसानों के साथ गिरफ्तार किया गया।

किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन ने एक–संयुक्त बयान में पुलिस कार्रवाई व अमराराम तथा अन्य की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग की। किसान सभा ने किसान नेताओं की बिना शर्त रिहाई व दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की माँग करते हुए 2 अप्रैल को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों का आहवान किया। किसान सभा पिछले 2 वर्षों से अवैध रूप स`चल रहे टोल नाके को हटाने की भी माँग कर रही है।

पश्चिम बंगाल

राज्यों से.....

(पृष्ठ 24 का शेष)

मई दिवस पर पंचायत चुनाव रखने के खिलाफ प्रतिरोध

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को पंचायत चुनाव कराने की राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के विरोध में, सीटू, एटक, इन्टक, यू.टी.यू.सी., एच.एम.एस., ए.आई.सी.सी.टी.यू., टी.यू.सी.सी. और फेडरेशनों के हजारों मजदूरों ने संयुक्त रुप से राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन किया। । टी.एम.सी. की अगुवाई वाली राज्य सरकार के परामर्ष से राज्य चुनाव आयोग ने 1 मई, 3 और 5 को तीन चरण पंचायत चुनाव अधिसूचित किया और जानबूझकर 12 जिलों में 50 प्रतिशत सीटों के चुनाव को 1 मई को तय किया। ट्रेड यूनियनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की और 1 मई को चुनाव कार्यक्रम से बाहर रखकर पंचायत चुनावों को पुर्ननिधारित करने की माँग का एक ज्ञापन पर सौंपा, और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने के मजदूरों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा।

गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामल चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को, 1 मई को मजदूरों को मई दिवस के अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है, मई दिवस के अधिकार को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कड़े संघर्षों, बलिदानों और शहादत के माध्यम से अर्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि मई दिवस के बदले में 2 मई की छुट्टी घोषित करने की मुख्यमंत्री की घोषणा मई दिवस की भरपायी करने का हास्यास्पद प्रयास है। सीटू राज्य अध्यक्ष सुभाष मुखर्जी, इन्टक के महासचिव अनादी साहू और रामन पांडे ने भी बैठक को संबोधित किया। ट्रेड यूनियनों ने मई दिवस को पंचायत चुनाव तिथि तय करने के खिलाफ कोलकाता में उच्च न्यायालय के समक्ष संयुक्त रूप से याचिका दायर की। याचिका सुनवाई के लिए लंबित है।

सीटू ने मई दिवस पर पंचायत चुनाव तय करने और हिंसा की निंदा की

11 अप्रैल को एक बयान जारी करके, सीटू ने आई.एल.ओ. सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता के दिन, मई दिवस पर पंचायत चुनाव तय करने के लिए पश्चिम बंगाल की टी.एम.सी. सरकार की निंदा की है। टी.एम.सी. सरकार ने मई दिवस को चुनाव कार्यक्रम से बाहर रखने के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियनों के अनुरोध का दमन किया है, जो मजदूर वर्ग और जनता के मूल लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति उसके सत्तावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसका यह रवैया वामपंथी उम्मीदवारों, नेताओं और समर्थकों पर हमलों और चोट पहुंचाने सहित हिंसा का सहारा लेने वाले टी.एम.सी. गुंडों को संरक्षित करने और अन्य लोगों को नामांकन पत्र जमा करने से रोकने और इसे वापस लेने के लिए मजबूर करने में भी प्रतिबिंबित होता है। मई दिवस को चुनाव तिथि तय करने के लिए टी.एम.सी. सरकार को चुनौती देने के मामले में सीटू ने पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियनों को पूरी तरह से समर्थन दिया; और उनके अधिकारों पर क्रूर हमलों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों, जन संगठनों और वामपंथी दलों के बहादुराना प्रतिरोध के लिए एकजुटता जाहिर की है।

उत्तरप्रदेश

राज्यों से

हरियाणा

आंगनवाड़ी कर्मियों के आन्दोलन की बड़ी जीत

सीटू व सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा ने पक्के रोजगार, 18000 न्यनूतम वेतन, पैंशन सहित रिटायरमंट लाभ, प्रमोशन आदि मांगों को लेकर 19 फरवरी, 2018 को आंदोलन शुरू किया था। राज्य की 50000 के करीब वर्कर्स व हैल्पर्स पूर्ण रूप से हड़ताल व आन्दोलन में उतरीं। यह अपने आप में ऐतिहासिक अवसर था। बीएमएस व एआईयूटीयूसी व इनसे संबंधित यूनियनों ने आन्दोलन को धोखा देते हुए 1 मार्च को सरकार के पाले में खड़े होकर समझौता कर वर्कर्स व हैल्पर्स का भारी नुकसान किया। एकताबद्ध होकर लड़ते तो जो मिला उससे कहीं ज्यादा मिल सकता था। बावजूद इसके जो मिला वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य में हुए आन्दोलन व 19 फरवरी से आंगनवाड़ीकर्मियों की पूर्ण हड़ताल के चलते 10 मार्च तक विभिन्न दौर की वार्ताओं के बाद राज्य की भाजपा सरकार को वर्कर्स व हैल्पर्स के वेतन में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को स्वीकार करना पड़ा। यह वर्कर्स व हैल्पर्स के मजबूत आन्दोलन की जीत है।

सरकार ने वर्कर्स को राज्य सरकार की आउटसोर्स पालिसी के पार्ट–1 की श्रेणी में शामिल करना स्वीकार किया है। यह बड़ी उपलब्धि है। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। हालांकि पक्का कर्मचारी बनने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। राज्य में पहले वर्कर्स को मानदेय 8140 रूपये मिलता था। मार्च 2017 से पहले यह केवल 7500 था। अब दो कैटेगरी बन गई हैं। अर्ध कुशल जिसमें 10 वर्ष तक कार्यकाल पर 10286 की घोषणा की है। कुशल श्रेणी में जिसमें 10 वर्ष से ज्यादा सेवाकाल की वर्करों को शामिल किया है को 11429 रूपये मिलेंगे। सरकार द्वारा वर्करों व मिनी आंगवाड़ी वर्करों को आउटसोर्स पालिसी के पार्ट–1 में डालकर पी.एफ व ईएसआई के तहत कवर करने की घोषणा की है। इसलिए इस निर्णय के बाद रिटायरमैंट लाभ व पैंशन की स्वतः व्यवस्था हो जाएगी। ईएसआई में कवर होने से वर्कर के पूरे परिवार के फ्री इलाज की व्यवस्था होगी।

हैल्पर्स को अभी तक मानदेय 3820 रूपये मिल रहा था। इस आन्दोलन में सरकार ने मान लिया कि उनको मार्च 2017 से ही 4070 रूपये के हिसाब से भुगतान होगा व अब फरवरी 2018 के बाद उनका मानदेय 5715 रूपये वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1850 रूपये है। जैसे ही हर 6 महीने बाद वर्कर्स के वेतन में महंगाई के आंकड़े जुड़कर वेतन बढ़ोतरी मिलेगी, उनके आधे की अपने आप बढ़ौतरी हो जाएगी। सीटू, सर्व कर्मचारी संघ व हमारी यूनियन ने ही हैल्पर्स को भी जिनकी संख्या 25000 से ज्यादा है, अकुशल श्रेणी में शामिल करने व कम से कम वर्कर्स के वेतन का 70 प्रतिशत देने पर काफी संघर्ष सरकार के साथ किया। सीटू की यूनियन ने सरकार से हैल्पर्स को, वर्कर्स के वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर देने यानि 5710 रूपये के अलावा हैल्पर्स को अतिरिक्त लाभ का प्रस्ताव दिया। जिसमें, 10, 20 व 30 वर्ष के सेवाकाल की तीन कैटेगरी बनाकर पहली कैटेगरी को 5 प्रतिशत, दूसरी कैटेगरी को 10 प्रतिशत व तीसरी को 15 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे दिया जा सकता है।

काम के दौरान मृत्यु पर वर्कर/हैल्पर के आश्रितों को कम से कम 3 लाख रूपये मुआवजे देने की बात हुई है। हैल्पर से वर्कर व वर्कर से सुपरवाईजर की प्रमोशन 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की बात मानी है। अब सरकार ने माना है कि केवल सीनियरटी के आधार पर ही प्रमोशन होगा। कोई टैस्ट या किसी प्रकार की शर्त नहीं होगी। उम्र की कोई

सीमा नहीं होगी। अगर रिटायरमैंट का महीना भी बचा है तो भी लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों का किराया बड़े शहरो में 5000, छोटे शहरों में 3000 व गांव में 750 रूपये होगा व इस ऑर्डर को हर हाल में बिना शर्त लागू करवाया जाएगा। गर्मी–सर्दी की छुटिया कम से कम 15–15 दिन मिलेगी। विभाग में समायोजित क्रेच वर्कर्स व हैल्पर्स को नियुक्ति पत्र व बकाया मानदेय दिया जाएगा। रिटायरमैंट लाभ व पैंशन के बारे में अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकार व विभाग जल्द ही इस बारे एक प्रस्ताव लेकर आएगा। इस दौरान आन्दोलन में रही किसी भी वर्कर व हैल्पर के वेतन का कोई पैसा नहीं कटेगा व किसी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं होगी।

सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ मांगों पर मुख्यमंत्री महोदय स्वयं विधान सभा में 5 मार्च को घोषणा कर चुके हैं। 10 मार्च को दोबारा हुई वार्ता में कुछ अन्य मांगो पर सहमति दी है। यूनियन ने आंदोलन व हड़ताल को केवल 1 महीने के लिए स्थगित किया है। यदि सरकार किसी भी मुद्दे पर ढ़ीला रूख अपनाती है, तो इस बीच पूरी सांगठनिक तैयारी करते हुए 10 अप्रैल के बाद फिर बड़ा आन्दोलन शुरू होगा। (योगदान :जयभगवान)

राजस्थान

मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ मजदूर एकजुट

जयपुर में 30 मार्च 2018 को राष्ट्रीय अनिल स्टील के गेट पर अनिल स्टील मजदूर संघ (सीटू) के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कारखाने को दिल्ली की कंपनी तरुण इंटरनेशनल द्वारा नीलामी में खरीदा गया है। कंपनी के नए मालिक ने आते ही कहा कि कंपनी घाटे में है इसलिए मजदूरों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना चाहिए और उन्हेंपहले जितना वेतन भी नहीं मिल सकता कंपनी में नए सिरे से नौकरी के लिए आवेदन करो और पुराना हिसाब किताब पुराना मालिक देगा। इसके के खिलाफ गेट पर बजे आमसभा की गई। और निर्णय लिया कि मैनेजमेंट की शर्तों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम अनिल स्टील के कर्मचारी हैं और देनदारियों की जिम्मेदारी नीलामी में तय की गई थी कि जो भी खरीदेगा वही तमाम बकाया मजदूरों को चुकाएगा। इसलिए मैनेजमेंट की मजदूर विरोधी नीतियों और मजदूरों के अधिकार को छीनने का जो प्रबंधक द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसे सहन नहीं किया जायेगा। वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं करने देंगे 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करेंगे तथा तमाम देनदारियां जो भी मजदूरों की बकाया है जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके जो पैसे, ग्रेजुएटी छुट्टियों के पैसे बोनस यह सब नए मालिक को देने होंगे! आम सभा को सीटू के प्रदेश सचिव और जिला महामंत्री भंवर सिंह शेखावत, यूनियन के महामंत्री कामरेड सरदार सिंह यादव, यूनियन के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मीणा, यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जमाल लाल जाट, सीटू जिला सचिव सरवन लाल कुमावत, भगवान सहाय, भँवर लाल, अनिल कुमार, सहित अनेक साथियों ने संबोधित किया।

पंजाब

भट्टा मजदूरों का प्रदर्शन

ईट भट्टों के मालिकों के द्वारा कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ लाल झंडा पंजाब भट्टा मजदूर यूनियन (सीटू) की ओर से लुधियाना में एक प्रभावी रैली व प्रदर्शन किया गया। ईट भट्टा मजदूरों ने लुधियाना के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के कार्यालय के बाहर भी जुझारू प्रदर्शन किया। रैली को लाल झंडा पंजाब मजदूर युनियन के महासचिव तरसेम जोधा, पंजाब सीटू के उपाध्यक्ष जतिन्दर पाल सिंह, सीटू के जी सी एम हनुमान प्रसाद दुबे व सीटू के जिले के नेताओं रामलाल, विनोद तिवारी, राम ब्रिश, गुरनाम गुरम ने संबोधित किया। सीटू ने चेतावनी दी कि यदि भट्टा मजदूरों की वाजिब मांगों व श्रम कानूनों की पालन नहीं की गई तो सीटू द्वारा आंदोलन को और तेज किया जायेगा।

मध्य प्रदेश

लम्बे संघर्ष के बाद आंगनबाड़ी कर्मियों की बड़ी जीत

प्रदेश के सभी जिलों से आयी आंगनबाड़ी कर्मियों के दो दिवसीय (27–28 फरवरी) महापड़ाव में उनका उत्साह तथा संघर्षों के प्रति दृढ़ता साफ दिख रही थी। मुख्यमंत्री द्वारा लगातार की जाती रही छलावेपूर्ण घोषणाओं, कमरतोड़ काम, असुरक्षित कार्यदशाओं और शर्मनाक मानदेय के खिलाफ उनका आक्रोश चरम पर था। पिछले एक साल से प्रदेश के स्तर पर संगठित रुप से तथा विभिन्न जिलों में स्वयंस्फूर्त तरीके से वे सड़कों पर उतरीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन (सीटू) ने इस आक्रोश को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पहले स्वतंत्र आंदोलन तेज किया और फिर उसे संयुक्त आंदोलन के रुप में व्यापक बनाने का सफल प्रयास किया।

सरकारी कर्मचारी का दर्जा तथा तब तक 18 हजार न्यूनतम वेतन, केन्द्र सरकार द्वारा योजनाबद्ध रुप से इस समूची परियोजना को कमजोर कर इसको निजी हाथों में सौंपे जाने की साजिशों का विरोध जैसे मुद्दे आंदोलन की मुख्य मांगों में शामिल थे। इस महापड़ाव आंदोलन के लिए मप्र सरकार के इशारे पर भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अनुमति देने से इंकार कर दिया। यूनियन द्वारा तय किया गया कि 'प्रशासन अनुमति दे या न दे महापड़ाव आंदोलन यादगारे शाहजंहानी पार्क' में ही किया जाएगा।

27 फरवरी से शुरू हुए इस महापड़ाव आंदोलन में तय हुआ कि यदि बजट में आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों, विशेषकर मानदेय में वृद्धि के संबंध में यदि कोई ठोस प्रावधान नहीं आया तो चरणबद्ध आंदोलन आगे बढ़ा दिया जाए जिसमें आंदोलन के चरणों में 4 मार्च बजट का पुतला दहन, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, 15 मार्च दोपहर से 16 मार्च तक सभी जिला मुख्यालायों में भूख हड़ताल और अप्रैल माह में भरे जाने वाले अतिमहत्वपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएएसआर) प्रोफार्मा भरने का बहिष्कार किया जाए।

28 फरवरी को बजट में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कोई स्पष्ट व ठोस घोषणा या प्रावधान न होने की खबर आई तो आंगनबाड़ी कर्मियों के बीच शिवराज की वर्षों से की जा रही छलावेपूर्ण घोषणाओं की कलई खुल गई। इससे आंगनबाड़ी कर्मियों को पक्का यकीन हो गया कि बिना लड़े न तो कुछ मिला है और न ही मिलेगा। जब आंगनबाड़ी फैडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊषा रानी ने आयोजक संगठनों की ओर से मंच से आगामी चरणबद्ध आंदोलन का प्रस्ताव रखा तो पार्क में हजारों की संख्या में मौजूद आंगनबाड़ी कर्मियों ने जोरदार नारों के साथ उसका अनुमोदन किया।

बजट में अस्पष्ट व अपर्याप्त घोषणा के विरोध में प्रदेश भर में 4 मार्च को जिला मुख्यालयों पर बजट और मुख्यमंत्री के पुतले जलाये गए। 8 मार्च से तमाम जिला मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए। 8–9–10 मार्च को प्रदर्शन हुए। अधिकांश जिलो में तीनों दिन कुछ जिलों में दो दिन तथा शेष जिलों में सिर्फ 8 मार्च को प्रदर्शन हुए। रीवा, जबलपुर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, अनुपपुर, उज्जैन, होशंगाबाद, बैतूल, दमोह, बालाघाट, इंदौर, कटनी, ग्वालियर व अन्य जिलों में प्रदर्शन हुए।

राज्य भर में हो रही प्रदर्शन की कार्यवाही कई स्थानों पर हड़ताल में भी तब्दील हो गयी। इसी दबाव में मुख्यमंत्री को 10 मार्च को आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ चर्चा हेतु आमंत्रण देना पड़ा।

संयुक्त आंदोलन में शामिल सभी संगठनों के अलावा आंगनबाड़ी कर्मियों के कुछ अन्य संगठनों को मुख्यमंत्री ने चर्चा हेतु आंमत्रित किया इनमें बीएमएस से जुड़े संगठन को बुलाना विशुद्ध राजनैतिक आधार पर था। मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दों को स्पष्ट व तार्किक रुप से रखने की पहल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन (सीटू) की महासचिव किशोरी वर्मा ने की। मुख्यमंत्री ने तमाम मांगों को जायज बताते हुए उनके समाधान हेतु एक माह का समय मांगा। और सभी संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील भी की। संगठनों ने स्पष्ट किया कि एक यदि एक माह में ठोस निराकरण नहीं हुआ तो और बड़ा व तीखा आंदोलन होगा। प्रतिनिधि मंडल में किशोरी वर्मा, पार्वती आर्य, माया भिलाला, गायत्री पटेल, साधना भदौरिया, विद्या खंगार, कमलेश शर्मा, हाजरा काजमी, शारदा पटेल, सलमा जेदी शामिल थी।

मुख्यमंत्री के एक माह के आश्वासन के बाद सीटू यूनियन सहित मोर्चे के अन्य घटकों ने कर्मियों को यह संदेश दिया कि यदि एक माह में ठोस निराकरण नही हुआ तो और बडे आंदोलन के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने आंगनवाडी यूनियनों को 29 मार्च को चर्चा के लिये पुनः बुलाया और आश्वस्त किया कि वह बेहत्तर निर्णय कर रहे हैं। इसके लिये मुख्यमंत्री ने ही 8 अप्रैल को भोपाल के किसी बडे मैदान में आंगनवाडी कर्मियों की महापंचायत बुलाने का सुझाव दिया।

सरकार ने पहले भोपाल के लाल परेड पुलिस ग्राऊन्ड में महापंचायत करने की घोषणा की तथा मानदेय वृद्धि आदि की की जाने वाली घोषणाओं का श्रेय भारतीय मजदूर संघ को देने की योजना बनायी। सीटू सहित तमाम यूनियनों द्वारा होने पर इसका विरोध उसने पंचायत के कार्यक्रम में ही बदलाव कर इसे मुख्यमंत्री निवास में करने व सीमित संख्या में आंगनवाडी कर्मियों को लाने व बी.एम. एस. का वर्चस्व दिखाने की योजना बनायी। इसके लिये उसने पंचायत के स्थान इसे पोषण उन्मुखीकरण का सरकारी कार्यक्रम बना दिया। इस साजिश को भी असफल करने आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन(सीटू) का नेतृत्व 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पहुंचा।

इस कार्यक्रम की सूचना गुपचुप जारी की फिर भी बडी संख्या में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहायिकायें भोपाल पहुंच गई। अधिकारियों ने उन्हें कार्यक्रम स्थल तक जाने से रोका। इससे गुस्साये कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास के मुख्य द्वार के सामने जमकर नारेबाजी की और सरकार द्वारा आंगनवाडी यूनिफार्म का सम्मान न करने के विरोध में कुछ कार्यकर्ताओं ने यूनिफार्म (साडी)भी जला दी। फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी तथा प्रदेश महासचिव किशोरी वर्मा ने भी हजारों आंगनवाडी कर्मियों के साथ सरकार द्वारा किये गये अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में की गई इस कार्यवाही का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व बी एम एस की मिलीभगत से आंगनवाडी कर्मियों को जबरन भगवा टोपी पहना कर कार्यक्रम के भगवाकरण करने की साजिश का विरोध कर इसे विफल भी किया। इस विरोध कार्यवाही के चलते प्रशासन को हजारों आंगनवाडी कर्मियों को मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश देना पडा।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित तथाकतिथ पंचायत (पोषण उन्मुखीकरण अभियान) में मुख्यमंत्री ने आंगनवाडी कर्मियों के मानदेय में बढोत्तरी कर कार्यकर्ता का मौजूदा मानदेय 5 हजार से बढाकर 10 हजार एवं सहायिका का मानदेय 2500 से बढाकर 5 हजार रुपये करने, आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने, सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए और सहायिका को 75 हजार रुपए देने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार की बेटी को नियुक्ति में 10 अंक की छूट देने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता–सहायिकाओं को बिना कारण हटाने पर रोक लगाने की व्यवस्था करने, बिना जांच के कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता–सहायिका को नही हटाने, दुर्घटना में मृत्यु की दषा में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं या सहायिका के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, वर्षों से कार्यरत अनुभवी व योग्य सहायिकाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन में वरीयता देने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यात्रा भत्ता देने, षासकीय सेवा में चयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को प्राथमिकता देने,अच्छा काम करने वाली कार्यकर्ताओं को दीनदयाल सम्मान देने की भी घोषणा की।

सीटू प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी, महासचिव प्रमोद प्रधान, आंगनवाडी फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊषा रानी, यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विद्या खंगार, महासचिव किशोरी वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेश शर्मा, कोषाध्यक्ष हाजरा काजमी ने लगातार संघर्ष और इससे मिली जीत के लिये प्रदेश की आंगनवाडी कार्यकर्ता सहायिकाओं को बंधाई देते हुये महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन लागू कराने और षासकीय कर्मचारी का दर्जा पाने के संघर्ष को जारी रखने का आह्वान किया है।

ओडिशा

न्यूनतम् वेतन के लिए विशाल विधान सभा कूच

9 अप्रैल को ओडिशा विधानसभा के समक्ष निर्माण, परिवहन, खानों, आंगनवाड़ी, आषा, मध्यान्ह भोजन, कृषक साथी, बैंक मित्र और अन्य जैसे असंगठित क्षेत्र से हजारों मजदूरों ने सीटू के नेतृत्व में राज्य स्तर के जुलूस, धरना और प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर शामिल हुए।

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई एक रंगारंग रैली ने विधानसभा की ओर कूच किया और पुलिस अवरोध पर पहुँचकर धरने में परिवर्तित हो गया और प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम एक ज्ञापन में 22 सूत्रीय माँगों में 18,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय करने और सभी योजना मजदूरों के कवरेज की मांग षामिल है; जल्द पंजीकरण और निर्माण मजदूरों को कल्याणकारी लाभों का वितरण; आउटसोर्स, कैजुअल, ठेका और सेवा प्रदाता मजदूरों का नियमितीकरण; समान काम के लिए समान बराबर वेतन; निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष आदि शामिल हैं। आंदोलन का मुख्य केन्द्र बिन्दु हालांकि, न्यूनतम वेतन में तत्काल वृद्धि पर था जो अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। श्रम मंत्री ने उचित स्तर पर निर्णय लेने के बाद राज्य के न्यूनतम वेतन बढ़ाने के प्रतिनिधिमंडल को आष्वासन दिया।

धरना स्थल पर जन सभा की अध्यक्षता लम्बोदर नायक ने की और राज्य के महासचिव बिरूनू मोहंती, उपाध्यक्ष शिवाजी पटनायक, पूर्व सांसद, राधारामन सारंगी, नाबा किशोर मोहंती, बिमान मैती, लोवाकांत स्वैन, उल्लाष स्वैन, रमेष जेना, सत्यानंद बेहरा , श्रीधर मिश्रा, इसाणी सारंगी, बनबासिनी महापात्रा, और अन्य ने सम्बोधित किया। पूर्ण चंद्र पाधी, सुरेष रूत्रे, संतोश बेहरा, चंदन आचार्य ने आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (द्वाराः रमेश जेना)

दिल्ली

डीएमसी ठेका मजदूरों की हड़ताल जीत के साथ समाप्त हुई

सीटू की एंटी–मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में, तीनों दिल्ली नगर निगमों (डीएमसी) के 3500 ठेका मजदूर, निवारक स्वास्थ्य कार्य में लगे हुए हैं और घरेलू प्रजनन जांचकर्ता (डीबीसी) के रूप में नामित हैं, अपनी नौकरियों नियमितीकरण करने और नियमित नौकरियों पर लागू अन्य सभी वैधानिक हितलाभों की मांगों को लेकर, 12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और 13 मार्च से क्रमिक भूख हड़ताल पर, यह आन्दोलन 28 मार्च को जीत के साथ समाप्त हुआ। हड़ताल 3 डीएमसी के सभी 12 जोनों में यूनियन की सदस्यता से पार थी। 1500–2000 पुरुष और महिला कार्यकर्ता अविभाजित डीएमसी के मुख्यालय, सिविक सेंटर के सामने दैनिक रूप से धरना और क्रमिक भूख हड़ताल में शामिल हुए।

सफाई मजदूर भी अपनी मांगों के साथ संघर्श में शामिल हो गए और सिविक सेंटर के सभी 7 प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया। कर्मचारियों ने काले झंडे दिखाए और अफसरों और काउंसिलरों के प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया। जल बोर्ड, निर्माण, आंगनवाड़ी, ऑफिस एण्ड एस्टेब्लिशमैन्ट, जनरल मजदूरों और बीमा सहित बिरादराना यूनियनों के नेताओं ने इस संघर्ष के साथ एकजुटता और समर्थन में धरना में शामिल हुए। एडवा और डीएसएमएम की दिल्ली राज्य कमेटियों के नेता भी समर्थन के लिए धरना स्थल पर आए। संघर्ष की सफलता को देखते हुए, बीएमएस यूनियन ने भी हड़ताल का समर्थन किया। बीजेपी, कांग्रेस और आप के दिल्ली राज्य के षीर्श नेता भी धरना स्थल पर आए और मांगों और हड़ताल का समर्थन किया। आप के काउंसिलर्स ने सिविक सेंटर के अंदर धरने का आयोजन किया। दोनों सत्तारूढ़ और विपक्षी काउंसिलर्स ने निगम के सत्रों में इस मुद्दे को उठाया।

हड़ताल के दूसरे दिन, सभी तीनों डीएमसी के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने यूनियन के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया और अदालत में इस मुद्दे पर लंबित याचिका के चलते नियमितीकरण को छोड़कर, मांगों पर सहमति व्यक्त की और समयबद्ध कार्यान्वयन का आश्वासन दिया था; और सहमत बिंदुओं पर लिखित मिनट देने से भी बचा गया। इस तरह, हड़ताल और आंदोलन जारी रहा।

आखिरकार, 28 मार्च को, सभी तीनों डीएमसी के प्रशासन ने लिखित मिनिटस् प्रदान किए और कार्यान्वयन आदेश जारी किए जिसके बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मिनिटस् और आदेशों में एनडीएमसी ने 4 महीने की सर्विस ब्रेक के प्रस्ताव को वापस ले लिया है; प्रत्येक महीने एक सी.एल. और सभी त्यौहार और राजपत्र छुट्टियों के लिए पात्रता; ईपीएफ और ईएसआईसी (सी) के तहत सभी कर्मचारियों का कवरेज; नौकरियों के नियमितकरण से संबंधित सभी दस्तावेज यूनियन जमा करेगी और सभी तीन डीएमसी एक महीने के भीतर जवाब देंगे। (द्वाराः अनुराग सक्सेना)

अंतर्राष्ट्रीय

रेलवे मजदूरों की 3 माह लम्बी आवृती हड़ताल

रेलवे के निजीकरण और कर्मचारियों के मौजूदा लाभों में कटौती की फ्रांसीसी सरकार की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन; राज्य के स्वामित्व वाली एस.एन.सी.एफ. में रेलवे की मजदूर यूनियनों ने 3 महीने की लंबी आवृत्ति हड़ताल शुरू की, 3 अप्रैल से हर 5 दिनों में 2 दिन की हड़ताल शुरू हुई और यह 28 जून तक जारी रहेगी।

पूर्व निवेश बैंकर राष्ट्रपति मैक्रॉन की सरकार का कहना है कि भारी–ऋणात्मक एसएनसीएफ को गहरे सुधार की जरूरत है क्योंकि यूरोपीय संघ के देश 2020 तक प्रतिस्पर्धा के लिए यात्री रेल खोलने के लिए तैयार हैं। और उस से रेल मजदूरों की नौकरियों की स्थायीता समाप्त हो जाएगी और मौजूदा हितलाभों को काटा जाएगा।

सरकार की प्रचार मिल ने एसएनसीएफ मजदूरों के काम को, 'काम की उदार स्थितियों का आनंद लेना' बताया। कैसे? चूंकि वे सेवानिवृत्ति की आयु तक नियोजित हैं, वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होती है, एक वर्ष में अर्जित सवैतनिक छुट्टी के 28 दिन, आश्रितों के लिए मुफ्त रेल पास और मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा मिलती है! मैक्रॉन सरकार इन 'विषेश एसएनसीएफ अनुबंधों' को समाप्त करना चाहती है, ठेके के आधार पर नई भर्ती करने का प्रस्ताव रखती है। दूसरी तरफ, यूनियनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि एसएनसीएफ की मौजूदा तीन इकाइयों को एक इकाई में विलय करके और उसका निगमीकरण करना निजीकरण का कदम पिछले दरवाजे से प्रयास है।

सीटू का बधाई संदेश

फ्रांस के सीजीटी के माध्यम से, सीटू ने 6 अप्रैल को फ्रांस के हड़ताली रेलवे मजदूरों को उनकी अद्वितीय और सफल आर्वती हड़ताल के लिए बधाई संदेश भेजा है और उनकी कार्रवाई के साथ हड़ताल और मुद्दे पर एकजुट समर्थन व्यक्त किया है।

सीरिया पर अमरीकी नेतृत्व में हमले की सीटू द्वारा निन्दा

16 अप्रैल को एक बयान में, सीटू ने असद सरकार के रासायनिक हथियार का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण उल्लंघन करने के आरोप के खिलाफ सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अवैध संयुक्त सैन्य हमले की निंदा की; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इस तरह अमेरिकी नेतृत्व के सैन्य हस्तक्षेप के संकल्प को अस्वीकार करने के बावजूद भी; और असद सरकार के निमंत्रण पर रासायनिक हथियारों के निशेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निरीक्षण से पहले ही किया गया है। बयान में कहा गया है कि यह साम्राज्यवादी प्राकृतिक संसाधनों और प्रभाव के क्षेत्रों को फिर से वितरित करने और सीरिया में चल रहे आतंकवादी समूह की मदद करने के प्रयासों का ही एक हिस्सा है।

सीटू का कहना है कि यह अकेले सीरिया के लोग हैं जिन्हें साम्राज्यवादियों के हस्तक्षेप किए बिना लोकतांत्रिक तरीके से अपने मामलों का फैसला करने का अधिकार है। सीटू ने इस तरह के हमलों की निंदा करने के लिए भारत सरकार से मांग की है।

सीटू ने, मजदूर वर्ग और सीरिया की जनता, जिन्हें अपने देश में साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों के कारण पीड़ित होने के लिए मजबूर किया गया है, के साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए देश के मजदूर वर्ग का आह्वान् किया है।

समर्थन और एकजुटता के लिए सीरिया के ट्रेड यूनियनों आह्वान्

इससे पहले, सीरिया के जनरल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (जीएफटीयू) ने देश के पूरे मजदूर वर्ग को एकजुट कर दिया, जिसे डब्लू. एफ.टी.यू., अरब ट्रेड यूनियनों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और उनके सहयोगियों से अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और समर्थन कार्रवाई के लिए और उनके लिए एकजुटता और संबंधित दूतावास के पास, अमेरिका और उसके सहयोगियों की निंदा करने के संदेश भेजने का आह्वान् किया है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों से सीरिया के खिलाफ आतंकवादी युद्ध को उकसाने के लिए ''यूएसए, यूके, फ्रांस और इस क्षेत्र में उनकी मुख्तारी करने वाले, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और अन्य जैसों'' पर आरोप लगाया है; और फर्जी प्रचार के साथ झूठे सबूतों सहारा लेते हुए, जिनमें झूठे और गढ़े हुए नवीनतम वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि पूर्वी घोटा में सफेद हेल्मेट्स पहने सीरियाई सेना द्वारा 'रासायनिक हथियार' द्वारा मारा गया, जबकि वे सीरिया में अल–नुसर आतंकवादियों के चिकित्सा विंग के हैं।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	tuojh 2018	Qojh 2018
vk/k in'k	x.Vj	280	277
	gnjkckn	251	251
	fo'kk[kkiÝkue	285	283
	okjxy	293	291
vle	MeMek frulf[k;k	258	258
	xokgkVh	250	249
	ycd flYpj	262	259
	efj;kuh tkjgkV	241	241
	jxkikjk rtij	241	241
fcgkj	e?kj&tekyij	306	305
p.Mhx<	p.Mhx<	287	287
NÝkhlx<	fHkykbl	314	312
fnYyh	fnYyh	267	266
Xkkvk	xkvk	303	306
Xkjkr	vgenkckn	269	268
	Hkkouxj	267	268
	jktdkV	277	276
	ljr	261	258
	oMknjk	268	265
gfj;k.kk	Qjhnkckn	261	275
	;euk uxj	275	256
fgekpy	fgekpy çn'k	270	270
tEe ,o d'ehj	Jhuxj	285	280
>kj[k.M	ckdkjk	310	308
	fxfjMhg	332	336
	te'kniij	319	317
	>fj;k	336	336
	dkMek	331	328
	jkph gfV;k	298	297
dukVd	cyxke	287	287
	cxykj	310	310
	gcyh /kkjokM	299	297
	ejdjk	300	299
	elij	298	295
djy	,.kkdlye@vyobl	301	300
	e.MkD;ke	325	326
	fDoyku	291	288
e/; çn'k	Hkkiky	293	292
	fNnokMk	264	261
	bnkj	288	288
	tcyij		

jkT;	dn	tuojh 2018	Qojh 2018
egjk"V	eEcbl	292	288
	ukxij	327	324
	ukfld	311	309
	i.k	289	289
	'kkykij	297	295
mMhlk	vkxy&rkypj	307	301
	jkmjdyk	308	305
	ikfMpfj	309	308
ikfMpfj	ikfMpfj	296	297
itkc	verlj	291	291
	tkyU/kj	278	277
	yf/k;kuk	267	265
jktLFkku	vtej	277	274
	HkhyokMk	274	269
	t;ij	266	271
rfeyukMl	pUul	267	289
	dk;EcVj	292	276
	dUuj	297	273
	enjkbl	271	284
	lye	287	292
	fr#fpjkiYyh	292	293
f=ijk	f=ijk	263	262
mÝkj çn'k	vkxjk	317	315
	xkft;kckn	292	292
	dkuij	298	299
	y[kuÅ	285	288
	okjk.klh	288	287
if'pe cxky	vklulky	310	309
	nkftfyx	270	272
	nxkij	310	309
	gfYn;k	317	316
	gkoMk	276	273
	tkyikbxMh	279	277
	dkydkrk	271	268
	jkuhxt	260	260
	flyhxMh	263	265
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		288	287

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्कः ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

15 मार्च का राष्ट्रीय विरोध दिवस

आंध्रप्रदेश

पंजाब

राजस्थान

बिहार

केरल

मई दिवस पर पंचायत चुनाव रखने के खिलाफ विरोध

(रिपोर्ट पृ० 19)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/05/2018)

आन्दोलनरत किसान

(रिर्पोट पृ० 18)

शिमला

आंध्रप्रदेश

लखनऊ, उत्तरप्रदेश

अलवर, राजस्थान में अमराराम की गिरफ्तारी

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : के हेमलता